साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 19 मई से 25 मई 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 10 में...
"सिनेमा" मतलब
'सीने में मां'

पेज 12 में...
EV पॉलिसी
धुंआ-धुंआ

वर्ष : 01 अंक : 11 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 07 क्या एक और सीजन खेलेंगे एमएस धोनी?

"चित्रोत्पला" की बुनियाद से पहले बहस

फिल्म सिटी 54 एकड़ में बनेगी | केंद्र सरकार ने 147.66 करोड़ रुपए दिया | राज्य शासन का अंशदान कितना? | बाकी फंड पीपीपी मॉडल से जनरेट करेंगे | केंद्र की राशि में बैंक ब्याज दर पर हुआ खेल | टेंडर 'ए क्लास' ठेकेदार को दिया जाएगा

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

फिल्म सिटी चित्रोत्पला की इबारत लिखी जा चुकी है साथ ही इसकी बुनियाद भी तय कर ली गई है। बस इंतज़ार है तो उस खुशकिस्मत निर्माणकर्ता की जो इसको तामीर करेगा। फ़िलहाल केंद्र सरकार से मिली करोड़ों रूपये की रकम और उसके ब्याज दर में ही अभी से बड़ा खेला कर दिया गया है। महज 2.75 फीसदी के कमतर ब्याज दरों में पर्यटन मंडल के एमडी आईएफएस विवेक आचार्य ने एचडीएफसी बैंक में पूरी राशि जमा कर दी है। अगर अन्य पंजीकृत बैंकों से उनकी ब्याज दरों को टेली कर राशि जमा की जाती तो एचडीएफसी द्वारा दी जा रही ब्याज राशि से डबल मिलता। इतने महत्वाकांक्षी योजना और केंद्र से प्राप्त राशि से शुरुआत में ही खिलवाड़ किया जाने लगे तो निर्माण और अन्य प्रक्रियाओं में कितनी उदासीनता बरतेंगे यह वक्त ही बताएगा।

फिल्म सिटी 54 एकड़ में तो कन्वेक्शन सेंटर 4 एकड़ में होगा

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिल्म मेकिंग और फिल्म टूरिज्म के लिए फिल्म सिटी निर्माण के माध्यम से अपार संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। इसके साथ ही पुरे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से प्राप्त राशि और राज्य सरकार से मिलने वाली मदद कितनी ईमानदारी से खर्च की जाएगी यह बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में मुलाकात कर छत्तीसगढ़ पर्यटन की अपार संभावना पर प्रकाश डाला था।

केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत राज्य की दो महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147.66 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अंतर्गत 95.79 करोड़ रूपए की लागत से माना तूता रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण तथा 51.87 करोड़ रूपए की लागत से माना तूता रायपुर में जनजातीय और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शामिल है।

स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत राजधानी रायपुर में फिल्म सिटी, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट और नेचर सिटी के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जिसके परिप्रेक्ष में फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 147.66 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

150 करोड़ का प्रोजेक्ट, पहली किश्त में मिले 100 करोड़

बताते हैं कि छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी के लिए केंद्र से प्रोजेक्ट के लिए आई केंद्र की राशि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को प्राप्त गई है। मजे की बात यह कि पर्यटन मंडल के एमडी विवेक आचार्य ने प्राप्त करोड़ों की राशि एचडीएफसी बैंक के खाते डाल दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म सिटी निर्माण के लिए अभी निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और एमडी श्री आचार्य ने बिना नियम-प्रक्रिया के केंद्र से मिली राशि एक काम ब्याज दर में एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में जमा कर दिया है। बता दें कि सरकारी पैसों को अपनी मर्जी से नियमों को ताक में रखकर केंद्र या राज्य की राशि को निजी बैंकों में नहीं रख सकते। उन्हीं निजी बैंकों में यह राशि रखने का नियम है जो सर्वाधिक ब्याज देयक हो।

100 करोड़ रूपये का ब्याज दर 2.75 प्रतिशत है

एचडीएफसी राखी केंद्र से प्राप्त फिल्म सिटी निर्माण की रकम तकरीबन 100 करोड़ रूपये है। इसे बैंक ने महज 2.75 परसेंट में रखा है। हिसाब लगाएं तो सालभर का इंट्रेस्ट एचडीएफसी से मात्र 2 करोड़ 75 लाख रूपये मिलेगा। जबकि अन्य ज्यादा ब्याज दर देयक बैंक में यह राशि रखते तो जस्ट डबल से भी ज्यादा ब्याज यानि कि करीबन 5 से 6 फीसदी ब्याज मिलता। लेकिन आईएफएस और पर्यटन मंडल के एमडी विवेक आचार्य ने सभी नियम और ब्याज दर को ताक में रख कर अन्य बैंकों से रेट ऑफ़ इंट्रेस्ट मंगवाए एचडीएफसी को करोड़ों रूपये सौंप दिया है।

मेकर्स के साथ-साथ दर्शकों को मिलेगी सुविधा

परिसर में दर्शकों के लिए एक्सपीरियंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। दर्शक फिल्म मेकिंग, एडिटिंग और शूटिंग देख सकेंगे। इसके साथ ही अपना कंटेंट भी शूट कर सकेंगे। दर्शकों को रील और वीडियो बनाने में परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। फिल्म की बेसिक स्ट्रक्चर में कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप, सेट-निर्माण, साज-सज्जा, कैमरा, फिल्म निर्माण उपकरण, ऑडियो प्रोडक्शन, डिजिटल पोस्ट प्रोडक्शन और फिल्म प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी।

एक्सपर्ट्स की परामर्शदात्री समिति गठित तो हुई लेकिन भुला दी गई

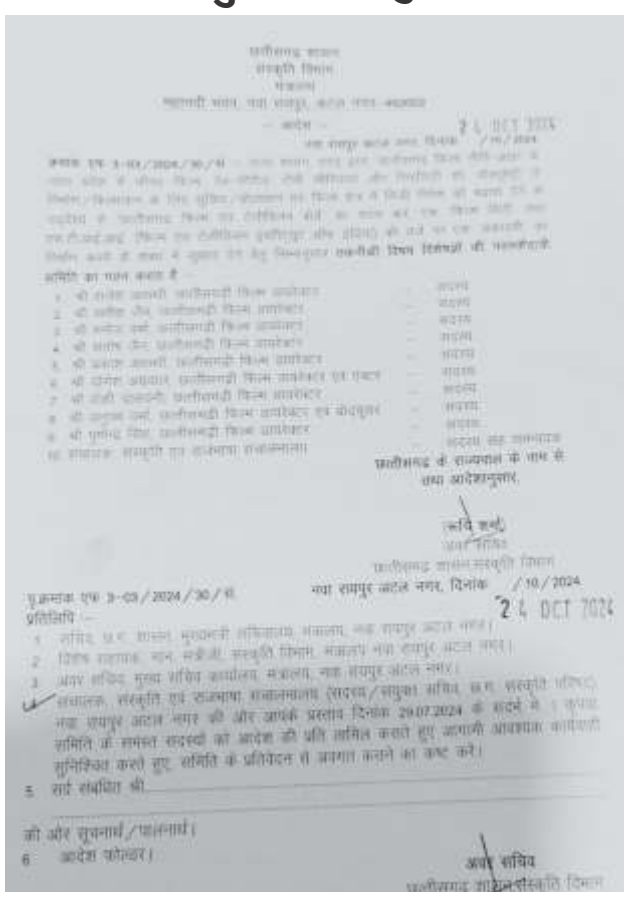

निर्माण में लोकल को तरजीह जरुरी

फिल्म सिटी चित्रोत्पला को आकार देने से पहले इस प्रोजेक्ट को लपकने के लिए देश के कई बड़े फिल्म निर्माता, प्रोडक्शन हॉउस मालिक लार टपकाते पहुँच रहे हैं। बोनी कपूर के अलावा हरमन बावेजा जैसी हस्ती पूरी शक्ति से इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने तत्पर है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी में प्रस्तावित फिल्म सिटी निर्माण के लिए लोकल को तरजीह मिले तो पैसों से लेकर रोजगार तक का लाभ स्थानीय को मिलेगा। लेकिन निर्माण निविदा की शर्तें ऐसी

बनाने की खबर है जिसमें बाहरी को ही काम मिलने की ज्यादा संभावना है। तुर्रा यह कि बड़े बजट और प्रोडक्शन हॉउस की फ़िल्में मुंबई, दक्षिण भारत की सर्वसुविधायुक्त फिल्म सिटी को छोड़कर यहां क्यों आएंगी।

अगर आई भी तो उनकी संख्या छालीवुड की फिल्मों की तर्ज में संख्या कमतर ही होगी। क्योंकि छालीवुड वाले काम ही आउटडोर शूटिंग में जाते हैं। इसलिए निर्माण और निविदा से लेकर आवश्यक जरूरतें स्थानीय फिल्म निर्माताओं के मुताबिक होनी चाहिए।

फिल्म सिटी निर्माण से यह मुनाफा

- छत्तीसगढ़ में पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर मिलेगी मजबूती
- ये योजनाएं रोजगार सृजन, विकास और छत्तीसगढ़ को पर्यटन मानचित्र में उकेरेगी
- फिल्म सिटी बनने के बाद स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर और रोजगार बढ़ेगा
- बॉलीवुड और साऊथ के बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस प्रदेश में आएंगे तो छालीवुड भी अपडेट होगा
- फिल्म सिटी बनने के बाद पर्यटकों की संख्या में और शार्ट फिल्मों समेत एल्बम में इजाफा होगा
- छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग को फायदा होगा, सरकार की आय भी बढ़ेगी

स्थानीय को मिले ज्यादा लाभ

- शूटिंग और सेट के किराये में छालीवुड को मिले रियायत
- निर्माण और सेटअप में छत्तीसगढ़िया लोकेशन को दें स्थान
- लोकल फिल्म प्रोडक्शन हॉउस को फिल्म सिटी निर्माण में रखें
- स्थानीय कलाकार, टेक्निशियंस और सीनियरों से ली जाये सलाह
- फिल्म निर्माण कार्य में श्रमिक से लेकर लोक कला में पारंगत को मिले रोजगार

इन सुविधाओं से लैस होगी हमारी फिल्म सिटी

- डिजिटल फिल्म निर्माण की सुविधाएं
- राजपथ
- होटल
- आउटडोर लोकेशन
- उच्च तकनीक से लैस प्रयोगशालाएं
- तकनीकी सहायता
- कृत्रिम जलप्रपात
- प्रोडक्शन हाउस
- 100 कमरों का होटल
- मल्टीपल रेस्टोरेंट
- कैफेटेरिया
- टिकट काउंटर
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
- हवाई अड्डा
- अस्पताल
- रेलवे स्टेशन
- एक्सपीरियंस सेंटर
- चर्च

छग.में शूट हुई हैं ये फ़िल्में-वेब सीरीज

■ अशोका ■ न्यूटन ■ चक्रव्यूह ■ ला वास्ते ■ बुद्धा इन ट्रैफिक जाम ■ चमन बहार ■ वेब सिरीज आर या पार ■ सावधान इंडिया ■ ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज

स्थानीय कलाकारों में ख़ुशी है और अंदेशा भी

चाहे बॉलीवुड हो या साउथ की फिल्में, आजकल छत्तीसगढ़ में शूटिंग का बोलबाला है। फिल्म की यूनिट प्रायः रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या बस्तर में कैमरा लेकर उतर रही है। ऐसा लगता है लोकल आर्टिस्ट्स और टेक्नीशियन को काम मिल रहा है, मगर हकीकत इसके उलट है। सिर्फ छोटे किरदार, कम पैसे या भीड़ के रूप में ही स्थानीय को लिया जाता है। और असली काम का सारा मौका बाहर से आए लोगों को मिलता है। 90% क्रू बाहर का, लोकल को सिर्फ भीड़ में खड़ा किया जाता है। टेक्नीशियन हो या स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट हो या कैमरा असिस्टेंट—हर विभाग में बाहरी का बोलबाला रहता है। और जो

लोकल हैं उन्हें बस आधे पैसे में एक लाइन का डायलॉग बोलने का मौका मिलता है या तो "भीड़ में खड़े कर दिया जाता है। माना जा रहा है कि भीड़ और बड़ी यूनिट्स आएंगी, लेकिन सवाल वही—काम किसे मिलेगा? जवाब साफ है—कुछ चुनिंदा लोकल सप्लायर्स और लोकेशन एजेंट्स को बचाखुचा काम मिलेगा और छोटे देखते रह जाएंगे। फिल्म नीति है, लेकिन लोकल के हिस्से में सिर्फ तालियां बजाना ही हैं अब तक। अगर शूटिंग हमारी जमीन पर हो रही है, तो क्रेडिट और काम भी हमें मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि "शूटिंग पर्यटन" बनकर रह जाये और लोकल टैलेंट के साथ एक और धोखा साबित हो।

प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सदस्यों को मिला आश्वासन

संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य से औपचारिक मुलाकात छत्तीसगढ़ सिने एवम टेलीविजन प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सदस्यों ने की थी। इस मीटिंग का उद्देश्य भविष्य में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को सब्सिडी दिए जाने संबंध में चर्चा की जानी थी। इस विषय पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया जिसमें फिल्म सिटी का प्रारूप कैसा होगा और किन किन लोकेशन को इसमें शामिल किया जाएगा। फिल्म सिटी का एक वॉकथ्रू भी दिखाया गया और भविष्य में एसोसिएशन की मदद से पीपीपी के अधिकार व्यक्ति के साथ बैठक कर आगे की कार्यवाई पूर्ण किए जाने का आश्वासन दिया गया है। सब्सिडी के संदर्भ में श्री आचार्य ने बताया कि बहुत जल्दी फिल्मों को सब्सिडी दिया जाना शुरू हो जाएगा। इस संदर्भ में उनके द्वार फ़ाइल मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दी गई है।

स्थानीय ठेकेदारों, आर्टिस्ट्स और इंडस्ट्री के लोगों को इस प्रोजेक्ट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और टैलेंट को पहले अवसर दिया जाना चाहिए। बल्कि स्थानीय को ही पूरे प्रोजेक्ट में प्रमुख स्थान दिया जाए। फिल्म सिटी का निर्माण सिर्फ छत्तीसगढ़ियों के हाथों से ही हो, तभी यह हमारे राज्य की असली पहचान बनेगी।

होमन देशमुख
छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता

फिल्म सिटी को लेकर हरमन बावेजा के उम्मीद भरे बोल

नया रायपुर भ्रमण के बाद हरमन बावेजा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रायपुर के बारे में मैंने जितना सोच रखा था उससे ज़्यादा ही पाया। यहां पर आज जिनसे भी मुलाकात हुई सब में अपनापन सा लगा। रायपुर की हवा में एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी है। यहां मैंने एक छत्तीसगढ़ी फ़िल्म की शूटिंग देखी। फ़िल्म सिटी को लेकर छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़े लोगों से विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई। नया रायपुर से लगा पुरखौती मुक्तांगन भी देखा। पुरखौती मुक्तांगन से मैंने छत्तीसगढ़ की कला व संस्कृति को समझने की कोशिश की। फ़िल्म सिटी पर संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अफसरों से बातचीत भी हुई। मेरा मानना है कि करीब 2 साल में फ़िल्म सिटी प्रोजेक्ट धरातल पर आ सकता है। फ़िल्म मेकिंग के नाम पर मैं और मेरा परिवार लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, पंजाब एवं गोवा जैसे स्थानों पर गया है। आज लगा कि जब हम उन स्थानों पर फ़िल्म शूट कर सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ के अपने पहले ही प्रवास में मैंने जाना कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां फ़िल्म पॉलिसी बन चुकी है और सरकार फ़िल्म निर्माण करने पर सब्सिडी भी देने जा रही है।

क्रेडिट चाहिए लेकिन सवालों का जवाब नहीं देते एमडी आचार्य

चंद रोज पहले छालीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के मुट्ठीभर लोगों को चर्चा के लिए पर्यटन मंडल के एमडी विवेक आचार्य ने अमंत्रटीत किया था। उनसे चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज के निर्माता, निर्देशक और अन्य लोगों में संतोष जैन, मनोज वर्मा, शैलेन्द्र दीवान, अनुमोद राजवैद्य और सिर्फ डॉ शांतनु पाटनवार पहुंचे थे। चर्चा के दौरान फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के प्रमुख अधिकारी आईएफएस विवेक आचार्य ने इस परियोजना को अपना "मिशन" बताते हुए कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार से दूर रहकर इस सपने को साकार करने में जुटा हूं। हमारा लक्ष्य है कि जून तक इस प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया जाए।"

योजना के संबंध में जब पर्यटन मंडल के एमडी और आईएफएस विवेक आचार्य से चंद सवालों के लिए समय मांगा गया तो उनके पीए दुर्गेश अग्निहोत्री से उनके मोबाईल नंबर 911009017 पर बात हुई और वो भी दो दिनों तक टालते रहे और उनकी अनुपस्थिति बताते रहे। बाद में कॉल ही रिसीव नहीं किये। टूरिज्म की पीआरओ शुब्दा चतुर्वेदी से भी जब संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इस सम्बन्ध में अग्निहोत्री से बात करने को कह कॉल काट दिया था।

सात साल बाद स्काई वॉक को मिलेगी रफ्तार

राजेश मूणत का बड़ा हमला: कांग्रेस ने लूटा छत्तीसगढ़, रायपुर में जल्द बनेगा स्काई वॉक

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अधूरी पड़ी स्काई वॉक परियोजना को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण जल्द शुरू होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर इस परियोजना को रोका।

मूणत के आरोप

रायपुर पश्चिम से विधायक राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने न केवल राज्य की जमीनों पर कब्जा किया, बल्कि रायपुर के विकास कार्यों को भी जानबूझकर रोक दिया। वर्ष 2016-17 में स्काई वॉक का निर्माण विधिवत टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से शुरू किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे रोक दिया। "भाजपा ने किया विकास, कांग्रेस ने किया विवाद": मूणत ने कहा कि जब भी भाजपा ने विकास की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया, कांग्रेस ने उसे केवल बहस का मुद्दा बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने कमल विहार, फ्लाईओवर और अंडरब्रिज जैसे कई विकास कार्य किए, लेकिन कांग्रेस ने हर बार राजनीति ही की।

स्काई वॉक की योजना: वर्ष 2016-17 में रायपुर के शास्त्री चौक से लेकर जय स्तंभ चौक और फिर जेल तिराहा तक स्काई वॉक का निर्माण प्रस्तावित था। इसका उद्देश्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना और पैदल चलने वालों के लिए सुविधा देना था। मूणत ने बताया कि पूरी स्टडी और सर्वे के बाद यह परियोजना स्वीकृत की गई थी। दो एजेंसियों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर निर्माण की योजना बनाई गई।

तीन बार हुआ प्रेजेंटेशन: मूणत ने बताया कि स्काई वॉक की रूपरेखा को लेकर तीन बार प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस की महापौर किरणमयी नायक, विधायक सत्यनारायण शर्मा, निगम अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस परियोजना को अधर में लटका दिया।

7 साल से अधूरी परियोजना: यह स्काई वॉक सात वर्षों से अधूरी पड़ी है। एसएन भावे एसोसिएट्स मुंबई द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार शास्त्री चौक से प्रतिदिन 27,000 और मेकाहारा चौक से 14,000 लोग पैदल चलते हैं। इसी आंकड़े के आधार पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने यह निर्णय लिया था। वर्ष 2017 में मेसर्स जीएस एक्सप्रेस लखनऊ को 42.55 करोड़ रुपये में कार्यादेश दिया गया था। स्काई वॉक की लंबाई लगभग 1.47 किलोमीटर तय की गई थी।

विवादों में घिरी लागत: निर्माण के दौरान इस परियोजना की लागत बढ़कर 77 करोड़ रुपये हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि परियोजना में बिना आवश्यक मंजूरी के कई संशोधन किए गए। दिसंबर 2017 में संशोधित लागत 81.69 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि मूणत ने 23 अप्रैल 2018 को परियोजना में 12 संशोधन किए, जिससे सिविल कार्य में 15.69 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत जुड़ गई।

भविष्य की उम्मीद: मूणत ने अंत में कहा कि भाजपा इस परियोजना को फिर से शुरू कराएगी और रायपुर को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि स्काई वॉक निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।

तेज रफ्तार, कमजोर नियम

नवा रायपुर बना एक्सीडेंट ज़ोन

आंकड़े जो डरा रहे हैं

- **राखी थाना:** 7 हादसे, 1 मौत, 6 घायल।
- **माना थाना:** 17 हादसे, 6 मौत, 12 घायल।
- **अभनपुर थाना:** 20 हादसे, 6 मौत, 26 घायल।
- **मंदिर हसौद थाना:** 34 हादसे, 15 मौत, 14 घायल।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। खासकर नवा रायपुर क्षेत्र अब 'डेंजर जोन' बन गया है। बीते 120 दिनों में सिर्फ चार थाना क्षेत्रों में 78 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। इनमें 28 लोगों की जान चली गई, जबकि 58 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसों की मुख्य वजह तेज रफ्तार, लापरवाही और नियमों की अनदेखी है।

- **4 महीने में 28 मौतें, हाईस्पीड और लापरवाही बनी जानलेवा**

हाईस्पीड से लेकर ड्रंक एंड ड्राइव तक

ट्रैफिक विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, नवा रायपुर के अभनपुर, माना, मंदिर हसौद और राखी थाना क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाईस्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव और कम जागरूकता इन हादसों के मुख्य कारण हैं। कई बार यात्री मालवाहक गाड़ियों में बैठते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। 11 मई को एक ऐसा ही हादसा हुआ, जिसमें मालवाहक वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हुए।

चल रहे अभियान लेकिन असर सीमित

एडिशनल एसपी ट्रैफिक के मुताबिक, पुलिस द्वारा मालवाहक वाहनों के चालकों और मालिकों के साथ कई दौर की मीटिंग ली गई है। उन्हें नियमों और जोखिमों को लेकर समझाया गया है। इसके अलावा हाईस्पीड वाहनों की निगरानी के लिए 10 प्रमुख सड़कों पर 40 हाईस्पीड फोकस कैमरे लगाए गए हैं। पिछले चार महीनों में 4800 तेज रफ्तार गाड़ियों का ई-चालान काटा गया और 6.10 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

आधी रात से सुबह तक जानलेवा हादसे

पुलिस रिपोर्ट बताती है कि रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए। इनमें 90 प्रतिशत हादसे गाड़ी के बिजली के खंभे, पेड़, रेलिंग या डिवाइडर से टकराने के कारण हुए। केवल 10 प्रतिशत हादसे दो वाहनों की टक्कर के चलते हुए।

सवाल खड़े करती है मौजूदा व्यवस्था

पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन आंकड़े साफ बताते हैं कि नतीजे अपेक्षित नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ सख्ती नहीं, बल्कि ट्रैफिक एजुकेशन, बेहतर सड़क डिजाइन और सख्त क्रियान्वयन की जरूरत है।

ट्रैफिक DSP बने 'गंगुआ', शॉर्ट फिल्म में रोकी बारात, जागरूकता का दिया संदेश

रायपुर। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक अलग और प्रभावशाली तरीका अपनाया है। ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म में बतौर अभिनेता नजर आए हैं। इस फिल्म में उन्होंने 'गंगुआ' नामक एक किसान की भूमिका निभाई है, जो मालवाहक गाड़ियों में लोगों के सफर के खिलाफ आवाज उठाता है।

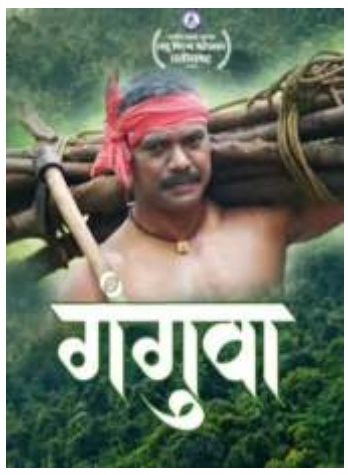

फिल्म के क्लाइमेक्स में गंगुआ यानी DSP ठाकुर एक बारात को रोक देते हैं, जो मालवाहक वाहन में सफर कर रही होती है। वे सभी को नियमों और संभावित खतरे के बारे में समझाते हैं, जिसके बाद बारात सवारी गाड़ी से आगे बढ़ती है। यह दृश्य रोड सेफ्टी के प्रति एक मजबूत संदेश देता है। हाल ही में खरोरा में हुई दुर्घटना, जिसमें मालवाहक वाहन और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की जान चली गई थी, इस फिल्म की प्रेरणा बनी। पुलिस और प्रशासन अब आउटर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

शारीरिक फिटनेस भी बनी चर्चा का विषय

इस फिल्म में DSP ठाकुर लुंगी पहने हुए एक देहाती किसान की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन उनके हैवी मसल्स और दमदार शरीर ने भी ध्यान खींचा। ठाकुर पिछले 25-30 वर्षों से नियमित व्यायाम कर रहे हैं। उनका मानना है कि पुलिसकर्मियों को फिट रहना बेहद जरूरी है।

SSP ने भी दिया संदेश

- फिल्म में रायपुर SSP डॉ. लाल उमेद सिंह भी नजर आए और उन्होंने वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि:
- मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं
- सभी दस्तावेज (लाइसेंस, बीमा, आर.सी., प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनेस आदि) वाहन में रखें
- नशे में वाहन न चलाएं
- ओवरलोड व ओवरस्पीड से बचें
- सीट बेल्ट लगाएं और सही लेन का उपयोग करें
- नो पार्किंग जोन में वाहन न खड़ा करें

हर साल जाती हैं डेढ़ लाख जानें

भारत में हर साल सड़क हादसों में औसतन डेढ़ लाख लोगों की जान चली जाती है। इन हादसों के बाद घायल को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाने से मृत्यु दर और बढ़ जाती है। 'गोल्डन आवर' यानी हादसे के 30 मिनट के भीतर मेडिकल सहायता मिलने पर जान बच सकती है। लेकिन कानूनी झंझटों के डर से लोग घायल की मदद करने से बचते हैं। इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से पुलिस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं।

जामनगर से लाये गए ज़ेब्रा की सर्पदंश से दर्दनाक मौत

शहर सत्ता/रायपुर। नया रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी में आज एक वयस्क नर ज़ेब्रा की साँप के काटने से मृत्यु हो गई। सर्पदंश यह ज़ेब्रा हाल ही में राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, जामनगर (गुजरात) से लाया गया था। संचालक जंगल सफारी थेजस शेखर ने बताया कि ज़ेब्रा को तुरन्त चिकित्सकीय सहायता दी गई, लेकिन सांप का विष उसके पूरे शरीर में फैलने की वजह से उसकी मौत हो गई। संचालक श्री शेखर ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक सुधारात्मक उपायों को अपनाने की बात कही है। सभी वन्यजीवों के निवास क्षेत्र में सर्प नियंत्रण और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

वर्ष 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का रोडमैप

छत्तीसगढ़ में माओवादियों पर सबसे बड़ा हमला

माओवादी ढेर, ऑपरेशन तेज़, शाह के मिशन को सच कर रहा छत्तीसगढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ जारी संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। बीते चार महीनों में राज्य ने माओवादी उन्मूलन की दिशा में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है। जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच 174 हार्डकोर माओवादी मारे जा चुके हैं—यानी हर महीने औसतन 43 माओवादियों का सफाया। यह आँकड़ा स्पष्ट संकेत देता है कि अब छत्तीसगढ़ अमित शाह द्वारा घोषित "2026 तक नक्सल मुक्त भारत" मिशन का अगुवा राज्य बन चुका है।

गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्षों में स्पष्ट रूप से कहा था कि नक्सलवाद एक 'राष्ट्रीय कलंक' है और इसे 2026 तक जड़ से खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। इस मिशन के तहत केंद्रीय सुरक्षा बलों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों की समन्वित रणनीति ने जंगलों में माओवादियों को लगातार पीछे धकेला है।

करेंगुट्टा ऑपरेशन: निर्णायक मोर्चा

इसी महीने बीजापुर जिले के करेंगुट्टा की पहाड़ियों में 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 माओवादी मारे गए। यह अब तक की सबसे लंबी और सघन कार्रवाई में से एक थी, जिसमें सुरक्षाबलों ने न केवल माओवादियों को मार गिराया, बल्कि उनके ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद और दस्तावेज भी बरामद किए। यह ऑपरेशन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह उस रणनीति का हिस्सा था, जो केंद्र सरकार ने उन क्षेत्रों में बनाई है जहाँ माओवादी अब भी प्रभावी हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे जिलों में अब माओवादी गुट छोटे-छोटे समूहों में बंटते जा रहे हैं, जिससे उनकी कमान और नेटवर्क दोनों कमजोर पड़ चुके हैं।

मानसून से पहले निर्णायक कार्रवाई

राज्य सरकार अब मानसून से पहले, यानी जून के दूसरे सप्ताह तक बीजापुर के अबूझमाड़ और नारायणपुर के माड़ क्षेत्र में बड़े स्तर पर ऑपरेशन की तैयारी में जुटी है। इन इलाकों को माओवादियों के अंतिम गढ़ के रूप में देखा जाता है। सुरक्षा बलों का उद्देश्य है कि बरसात से पहले इन दुर्गम इलाकों में घुसपैठ कर शेष बचे नेटवर्क को खत्म किया जाए।

केंद्र–राज्य समन्वय से मिल रही सफलता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच लगातार संवाद और तालमेल इस सफलता के पीछे अहम वजह माने जा रहे हैं। राज्य सरकार न केवल सैन्य स्तर पर सक्रिय है, बल्कि विकास की गति भी तेज़ कर रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को माओवाद प्रभावित गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों का भरोसा सरकार में बढ़ा है और वे अब माओवादियों का साथ छोड़ रहे हैं।

2026: खत्म होगा माओवाद का अस्तित्व

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा रणनीति यदि इसी गति से जारी रही, तो आने वाले 12 से 18 महीनों में छत्तीसगढ़ सहित पूरा भारत नक्सल मुक्त हो सकता है। अमित शाह के नेतृत्व में चल रहा यह मिशन अब सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि ज़मीन पर उतरता हुआ परिणाम है। नक्सलवाद पर निर्णायक चोट का वक्त आ चुका है। एक तरफ जंगलों में माओवादी मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाँवों में स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं और युवाओं को नौकरी के मौके मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ माओवाद से लड़ नहीं रहा, वह उसके विकल्प भी बना रहा है—शांति, विकास और आत्मनिर्भरता।

कर्रेगुट्टा ऑपरेशन पर गरमाई सियासत: विजय शर्मा का राहुल गांधी पर गंभीर आरोप

नक्सल ऑपरेशन में सहयोग नहीं मिला, राहुल गांधी पर शक: विजय शर्मा

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में नक्सलियों को हर मोर्चे पर शिकस्त मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के दौरान हमारे जवानों ने बेहद बहादुरी के साथ माओवादियों का सामना किया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हौसला बनाए रखा। इसी साहस की बदौलत ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली।

राहुल गांधी पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं

विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक और गंभीर आरोप लगाया। जब उनसे पूछा गया कि तेलंगाना सरकार ने कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ को अपेक्षित सहयोग क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। गृहमंत्री ने कहा, "मुझे स्पष्ट इस बात का आभास है, कुछ जानकारियां हैं, जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी देश की ऐसी समस्याओं, जिनमें नक्सलवाद भी शामिल है, को लेकर स्पष्ट नहीं हैं। वह पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं।" विजय शर्मा ने दावा किया कि उनके पास राहुल गांधी के खिलाफ इस संबंध में प्रमाण मौजूद हैं।

तेलंगाना सरकार की भूमिका पर सवाल

गृहमंत्री ने संकेत दिए कि कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के दौरान छत्तीसगढ़ को जो मदद मिलनी चाहिए थी, वह तेलंगाना सरकार से नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या पर सभी राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप ऐसे ऑपरेशनों को प्रभावित करते हैं। विजय शर्मा अपने दो दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। इस दौरान वे सुकमा के चिंगावरम पहुंचे, जहां 17 मई 2010 को आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने उपरोक्त बातें कहीं।

नक्सल क्षेत्र मोहला-मानपुर को नई सौगात

आईटीबीपी ने खोला पहला पशु अस्पताल

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मोहला-मानपुर क्षेत्र के सीतागांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने एक सराहनीय पहल करते हुए पहला पशु फील्ड अस्पताल स्थापित किया है। यह अस्पताल न केवल पशुओं की देखरेख के लिए एक नई शुरुआत है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आमजन से जुड़ाव और विश्वास कायम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

आईटीबीपी की 27वीं बटालियन ने की शुरुआत

शनिवार को आईटीबीपी की 27वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर विवेक कुमार पांडे ने सीतागांव में इस पशु अस्पताल का उद्घाटन किया। यह इलाका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। अस्पताल में एक पंजीकरण डेस्क, दवा वितरण केंद्र, उपचार कक्ष और बड़े जानवरों के लिए एक बाड़ा बनाया गया है।

12,000 से अधिक पशुओं को मिलेगा लाभ

कमांडिंग ऑफिसर पांडे ने जानकारी दी कि यह फील्ड अस्पताल सीतागांव और आसपास के करीब 20 गांवों के लगभग 12,000 पशुओं की देखभाल करेगा। इनमें मुर्गियां, बकरियां, गाय, बैल, सूअर और कुत्ते शामिल हैं। अस्पताल में नियुक्त पशु चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ मुफ्त में जांच और इलाज की सुविधा प्रदान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालना न केवल परंपरा है, बल्कि आजीविका का भी मुख्य आधार है। मुर्गी, गाय-बैल, बकरी और सूअर जैसे पशु ग्रामीणों की आर्थिक स्थिरता का प्रमुख स्तंभ हैं।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

बंद करें विष वमन

देश की दंड व्यवस्था के तहत जहां 'हेट स्पीच' या बिगड़े बोल को नये सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। उससे कहीं ज्यादा राष्ट्रीय चरित्र एवं राजनीतिक चरित्र निर्माण के लिए नेताओं और उनके दलों को आचार संहिता के बंधन में बांधना ही होगा। तभी "राजनीतिक सिस्टम" की रोग मुक्ति, स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का आधार बनेगा। बड़ा प्रश्न है कि क्या धर्म और जाति के नाम पर वोट के लिए सेना और सेना से जुड़ी बेटियों के सम्मान को चोट पहुंचाई जाना उचित है? चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष वाणी का संयम अपेक्षित है। भारतीय राजनीति में बिगड़े बोल, असंयमित भाषा एवं कड़ावपन की मानसिकता चिन्ताजनक है। ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक सड़कछाप भाषा ने अपनी बड़ी जगह बना ली है। यह ऐसा समय है जब शब्द सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके दुरूपयोग की घटनाएं लगातार जारी हैं।

हमारा देश पाकिस्तान से बदला लेने की शौर्य की महत्वपूर्ण घटना के मोड़ पर खड़ा है, तब कुछ नेताओं के बिगड़े बोल बहुत दुखद और निंदनीय हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के एक मंत्री विजय शाह एवं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव के खिलाफ जनता का गुस्सा स्वाभाविक है। विजय शाह को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग तेज हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विजय शाह की विवादास्पद टिप्पणी एक ऐसा दाग है, जिसे आसानी से नजरंदाज नहीं किया जा सकता। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और मामला भी दर्ज हो तो आश्चर्य नहीं। देश के नेताओं व मंत्रियों को ऐसी हल्की और स्तरहीन बातों से परहेज करना चाहिए।

यह सही है कि शब्द आवाज नहीं करते, पर इनके घाव बहुत गहरे होते हैं और इनका असर भी दूर तक पहुंचता है और देर तक रहता है। इस बात को राजनेता भी अच्छी तरह जानते हैं इसके बावजूद जुबान से जहरीले बोल और शाब्दिक विष वमन सामने आते ही रहते हैं। देश अभी-अभी एक संघर्ष से निकला है। यह एकजुटता और परस्पर समन्वय बढ़ाने के लिए संभलकर बोलने का समय है। राष्ट्रीय एकता एवं राजनीतिक ताने-बाने को ध्वस्त कर रहे जहरीले बोल की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। संकीर्णता एवं राजनीति का उन्माद एवं 'हेट स्पीच' के कारण न केवल विकास बाधित हो रहा है, सेना का मनोबल प्रभावित हो रहा है, बल्कि देश की एकता एवं अखण्डता भी खण्ड-खण्ड होने के कगार पर पहुंच गयी है।

कोंदा-भैरा के गोठ

-परोसी राज मध्यप्रदेश म अभी उजबक बोली ले गंदगी बगराय के प्रतियोगिता चलत हे जी भैरा.

-वाह जी कोंदा.. गंदगी बगराय के घलो प्रतियोगिता होथे गा!

-राजनीति म सब संभव होथे संगी.. अउ ए बुता ल कोनो अलवा-जलवा मनखे मन नहीं, भलुक उहाँ के मंत्री मन करत हें.

-ताज्जुब लागथे बुजा ह!

-हव.. पहिली उहाँ के वरिष्ठ केबिनेट मंत्री विजय शाह ह भारतीय सेना म कैप्टन सोफिया कुरैशी के संबंध म अनफभिक गोठ करे रिहिसे अउ अब उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ह 'बेवड़ा' मन असन गोठियाय हे.

-अच्छा.. देवड़ा ह बेवड़ा माने दरुहा मँदहा मन असन गा?

-हहो.. वो ह आपरेशन सिंदूर के पूरा श्रेय ल प्रधानमंत्री ल देवत ए कहे हे- 'पूरा देश अउ देश के सेना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चरण म नतमस्तक हे.'

-राजनीतिक चापलूसी के घलो एक मर्यादा होथे गा..फेर ए बुजा ह तो वोकरो ले अगुवाय बानी करे हे.

-हव भई.. चरण वंदना के परंपरा ल निभावत उँकर पार्टी के लोगन भले अइसन कर सकथे फेर पूरा देश अउ सेना के बात ह अनभरोसिल अउ अनफभिक हे.

'नापाक' 'परमाणु मुखौटा' उतर चुका है

पलकी शर्मा

पिछले दो दशकों से एक मिथक भारत और पाकिस्तान के तमाम टकरावों पर हावी रहा है- यह कि इस्लामाबाद के पास परमाणु हथियार हैं। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, जब पहले भारत परमाणु शक्ति बना और उसके बाद पाकिस्तान। तब से इस्लामाबाद एक ही नैरेटिव को पकड़े हुए है। इसे रावलपिंडी के जनरलों ने गढ़ा था। यह तथ्य कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, इस बात का लाइसेंस मान लिया गया कि वह आतंकवाद का निर्यात कर सकता है। 2001 के संसद हमले से लेकर 2008 के मुंबई हमलों तक, पाकिस्तान लगातार भारत को चोट पहुंचाता रहा और भारत ने भी डोजियर्स और डिप्लोमेसी के साथ सावधानी से जवाब दिया। लेकिन कभी सैन्य कार्रवाई नहीं की।

2016 के उरी हमले के बाद यह बदल गया। भारत ने नई मिसाल कायम की कि तुम हमला करोगे, तो हम पलटवार करेंगे। 2019 में- पुलवामा हमले के बाद- भारत ने इस स्थिति को और मजबूत किया। अब पहलगाम के बाद, और बड़ा बदलाव आया है। अब आतंकवाद के किसी भी कृत्य को युद्ध के रूप में देखा जाएगा। पाकिस्तान अब अपने परमाणु हथियारों के पीछे नहीं छिप सकता। उसे नतीजे भुगतने होंगे।

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। हमने उनके नागरिकों या सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि तनाव बढ़े। लेकिन पाकिस्तान इस मामले को तूल देना चाहता था और वह भी भारतीय नागरिकों पर निशाना साधकर। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें उलटी पड़ गईं। भारत ने जोरदार जवाबी हमला किया। उसने न केवल पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा में सेंध लगाई, बल्कि उनके परमाणु कवच के मिथक को भी जमींदोज कर दिया।

भारत नो-फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, जिसका मतलब है कि हम अपने परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकने के लिए नहीं थे। वे भारत को कुछ भी करने से रोकने के लिए थे। आतंकवाद के खिलाफ किसी जवाबी कार्रवाई को एटमी युद्ध को उकसावा देने के चश्मे से देखा गया। यह लगभग एक स्ट्रैटेजिक-वीटो की तरह था। पाकिस्तान अपने युद्धों को नॉन-स्टेट एक्टर्स को आउटसोर्स करके खुद बेगुनाह होने का दिखावा कर सकता था।

भारत और दुनिया परमाणु-प्रतिक्रिया के अंदेशे से उसे ऐसा करने की छूट भी देते रहे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के इस फरेब का पर्दाफाश कर दिया है। डिटरेंस की नीति तभी कारगर होती है, जब दोनों पक्ष तर्कसंगत हों। पाकिस्तान ने तो उलटे बेतुकेपन को ही अपना हथियार बना लिया है। भारत ने 1974 में जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो इसे 'बुद्ध मुस्कराए' कहा था। लेकिन इसने पाकिस्तान को भी एटमी हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान का नेतृत्व जुल्फिकार अली भुट्टो कर रहे थे। उन्होंने कहा था, हम घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। उन्होंने इसे मुसलमानों के लिए एक परमाणु-कवच की तरह मुस्लिम-दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन अब यह नैरेटिव तार-तार हो चुका है। क्योंकि, यह इस्लाम नहीं पाकिस्तान के बारे में था। वह अपने आतंक के कारखानों के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहा था।

भारत ने यह भी दिखाया है कि छद्म युद्ध अब पाकिस्तान के लिए सस्ता सौदा नहीं रह गया है। उन्हें आतंकवाद को समर्थन देने की कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान में फौज ही मुल्क की कमान संभालती है। इस फौज का यह रिकॉर्ड है कि इसने हर युद्ध हारा है। लेकिन वह अपने मिथकों के कारण शक्तिशाली बनी हुई है। इस संघर्ष के दौरान भी उसने यही रणनीति अपनाई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने परमाणु युद्ध की ओर संकेत किया। समाचार-एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान की शीर्ष परमाणु संस्था की बैठक होने वाली है। यह कवायदें नाकाम रहीं।

ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि परमाणु हथियार आतंकवाद को छिपाने का जरिया नहीं हो सकते। आप निर्दोष नागरिकों की हत्या करके दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जब कोई आपको जवाबदेह ठहराने की कोशिश करता है तो आप महाविनाश की ओर संकेत नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भी जवाब देगा। यही न्यू नॉर्मल है। बुनियादी बदलाव यह हुआ है कि अब भारत पाकिस्तान की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं खेल रहा है। जब आप दुश्मन के फरेब का खुलासा करते हैं तो खेल हमेशा के लिए बदल जाता है।

पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। उसका परमाणु-मुखौटा उतर चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। लेकिन भारत ने दिखाया है कि परमाणु हथियारों के बावजूद पाकिस्तान को दंडित किया जा सकता है।

'सिंदूर' ने स्त्रियों के मर्म को छू लिया है

नीरजा चौधरी

कुछ ऐसी छवियां होती हैं, जो लोगों के दिलो-दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं- और अक्सर किसी राष्ट्र के अस्तित्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण को कैद कर लेती हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सिर्फ 25 हिंदू पुरुषों की ही हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उनका धर्म जानने के बाद उनकी हत्या की गई थी। यह हिंदू महिलाओं के 'सुहाग' पर भी हमला था! किसी भी हिंदू विवाहित महिला को दिया जाने वाला सबसे बड़ा आशीर्वाद आमतौर पर 'सदा सुहागन रहो' ही होता है।

बिहार में छठ पूजा के समय पवित्र सिंदूर माथे से लेकर नाक तक लगाया जाता है- इसे एक आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में भी 'सिंदूर खेला' एक प्रसिद्ध पर्व है, जो दुर्गापूजा के अंतिम दिन मनाया जाता है। पूरे भारत में महिलाएं सिंदूर को अपनी वैवाहिक पहचान के प्रतीक के रूप में पहचानती हैं और पति के परिवार में स्वीकृति के रूप में भी। कुछ लोग इसे पितृसत्ता के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं, लेकिन विवाहित महिलाओं के एक बड़े समूह के लिए यह उनकी मूल पहचान का प्रतीक है। इसी सिंदूर पर आतंकवादियों ने प्रहार किया था।

इसके जवाब में जब भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक की गई तो उसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया। ऐसा करके भारत की सेना और सरकार ने हिंदू महिलाओं सहित पूरे देश के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव स्थापित कर लिया है। आखिरकार, पहलगाम में आतंकवादियों ने पति के साथ उसे भी मार डालने की गुहार लगाने वाली एक महिला से कहा था कि 'हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बता देना।' 25 में से अनेक विवाहित महिलाओं ने अपने पतियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। उनका सिंदूर- जो सबसे पहले विवाह समारोह के दौरान उनके पति द्वारा लगाया जाता है- कुछ ही क्षणों में मिटा दिया गया।

यही कारण था कि पहलगाम के बाद देश में जैसा गुस्सा था, वैसा हाल के दिनों में अन्य आतंकी हमलों के बाद नहीं देखा गया। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के इस नामकरण को भारत की महिलाओं की सुरक्षा, उनके नुकसान का बदला लेने तथा दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने की शपथ के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पीड़ित हिंदू महिलाओं के बारे में ही नहीं था, यह भारत के विचार के बारे में भी था- जो पाकिस्तान के एक मजहबी-राष्ट्र की पहचान से अलग था।

पहलगाम हमले से ठीक पहले पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों से आग्रह किया था कि वे कभी न भूलें पाकिस्तान का जन्म दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था और हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन 8 मई को जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की अधिकृत सूचना देश को दी तो इसके लिए दो महिलाओं को चुना गया- थलसेना में कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना में विंग कमांडर व्योमिका सिंह। एक मुस्लिम और एक हिंदू थीं!

उन्हें 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 25 मिनट तक चले भारत के सैन्य अभियान के बारे में देश और दुनिया को बताने के लिए चुना गया। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बैठे थे, जो अधिक तथ्यात्मक और संतुलित तरीके से अपनी बात कह रहे थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में भारत की महिलाओं के स्त्रीत्व की क्षति हुई थी! जब भारत ने उसका प्रतिशोध लिया तो ये भारत की सैन्य महिलाएं ही थीं, जो उनके साथ खड़ी नजर आई थीं- और आगे बढ़कर देश का नेतृत्व कर रही थीं। वे यह संकेत भी दे रही थीं कि भारत एक गौरवशाली, बहुलतावादी राष्ट्र है। यह एक ऐसा विचार है, जिस पर यह देश आधारित था और जिससे इसे शक्ति मिलती है।

ऑपरेशन सिंदूर- जिसने भारत की महिलाओं के विश्वासों- और शक्ति- को गहराई से छुआ है- आतंकवादियों और उनके समर्थकों को 'बस बहुत हो गया' का संकेत दे गया है। यह राजनीति और उसके नतीजों के बारे में बात करने का समय नहीं है, लेकिन सिंदूर की प्रतीकात्मकता से पूरे भारत में महिलाओं के मर्म को जैसे छुआ गया है, उसका प्रभाव निकट भविष्य में तो कम होने की संभावना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की महिलाओं के विश्वासों और शक्ति को गहराई से छुआ है। यह राजनीति और उसके नतीजों पर बात करने का समय नहीं है, लेकिन सिंदूर की प्रतीकात्मकता ने पूरे भारत में महिलाओं के मर्म को स्पर्श किया है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

ज्योति मल्होत्रा कैसे बनी पाकिस्तानी जासूस?

सामने आई स्पॉन्सर्ड ट्रिप और पाक का 'एसेट' बनने की कहानी

नई दिल्ली। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी और आईएसआई के तीन अधिकारियों के संपर्क में थी. साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी उसे एसेट के रूप में इस्तेमाल करती थी. इस बात की जानकारी रविवार (18 मई, 2025) को हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने दी.

उन्होंने मीडिया को ये भी बताया कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंट भारत के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का इस्तेमाल अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. सावन ने कहा, "आधुनिक युद्ध केवल सीमा पर ही नहीं लड़े जाते. पीआईओ कुछ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों की भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसका इस्तेमाल अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं. हमें केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिले और हमने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया. वह कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन जा चुकी थी. वह पीआईओ के संपर्क में थी. हमने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है."

आईएसआई अफसरों के संपर्क में थी ज्योति

पुलिस अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि ज्योति मल्होत्रा हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी. उन्होंने कहा, "हम उसके वित्तीय विवरण का विश्लेषण कर रहे हैं. संघर्ष (भारत-पाक) के दौरान, वह पीआईओ के संपर्क में थी. उसकी यात्रा का विवरण उसकी कुल आय को गलत साबित कर रहा है."

स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर जाती थी पाकिस्तान

एसपी ने यह भी खुलासा किया, "वे उसे (ज्योति मल्होत्रा) एक एसेट के रूप में विकसित कर रहे थे. वह अन्य यूट्यूबरों के भी संपर्क में थी और वे भी पीआईओ के संपर्क में थे. वह स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी. वह पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान में थी और अगर कोई संबंध है तो उसे स्थापित करने के लिए जांच जारी है. हम भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सुराग हैं कि अन्य लोग भी उसके साथ शामिल थे."

पहलगाम हमले से कनेक्शन

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. रविवार (18 मई, 2025) को हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तब ज्योति पाकिस्तान के हाई कमीशन के दानिश के संपर्क में थी. उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस को सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, जिसके आधार पर हमने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया. वो कई बार पाकिस्तान जा चुकी है, चीन भी गई है. फिलहाल उसे 5 दिन की रिमांड पर रखा गया है.

क्या बोले ज्योति के पिता

पाकिस्तान जाने के सवाल पर ज्योति के पिता ने कहा कि मेरी बेटी एंबेसी से परमिशन लेकर गई थी. जासूसी के सवाल पर उनके पिता ने कहा कि जब कोई कहीं बाहर जाता है तो क्या उसके दोस्त नहीं बन सकते. मेरी बेटी भी पाकिस्तान में अपने दोस्त से ही बात करती थी. वो लोग आपस की ही बात किया करते थे।

पाकिस्तान में मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर

इस्लामाबाद। ऑपरेशन सिंदूर से सदमे में आए पाकिस्तान के आतंकियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. आरएसएस मुख्यालय नागपुर पर 2006 में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने वाला लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू सैफुल्लाह पाकिस्तान में मारा गया. लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अबू सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर ढेर कर दिया. लश्कर का ये आतंकी अबू सैफुल्लाह नेपाल के जरिए आतंकी नेटवर्क को हैंडल कर रहा था. अबू सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मतली फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला. लश्कर का ये आतंकी भारत में तीन आतंकी हमलों में शामिल था. लश्कर के इस आतंकी का नाम अबू सैफुल्लाह उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ राज़ूल्लाह निज़ामनी था. जानकारी के मुताबिक ये नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा का पूरा मॉड्यूल संभालता था. इसका मुख्य काम लश्कर की आतंकवादी गतिविधियों के लिए कैडर और आर्थिक मदद मुहैया कराना था. ये आतंकी नेपाल के रास्ते लश्कर के आतंकवादियों को भारत में भेजने का भी काम करता था. इसने नागपुर में संघ मुख्यालय पर 2006 में हुए हमले में भी मुख्य भूमिका निभाई थी. इसके अलावा सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर 2001 में हुए हमले में भी इसकी बड़ी भूमिका थी. आईआईएससी बेंगलुरु पर 2005 में हुए हमले की साजिश में भी ये शामिल था.

कौन था अबू सैफुल्लाह?

लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह भारत में आतंकी हमले करवाने का काम करता था. भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अबू सैफुल्लाह को मोस्ट वांडेट आतंकियों की लिस्ट में डाल रखा था. इसी के चलते वो नेपाल छोड़कर वापस पाकिस्तान भाग गया था।

RSS और मुसलमान समंदर के दो किनारे, जो कभी नहीं मिल सकतेः ओवैसी

हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को "बेतुका" बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि आरएसएस और मुसलमान समंदर के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते. वैसी ने यह भी कहा कि आरएसएस भारत की विविधता को नष्ट करना चाहता है. उन्होंने शनिवार (17 मई,2025) को 'पीटीआई वीडियो' को दिए साक्षात्कार में कहा, "आप भले ही नजदीकी बताने वाली बातें कर रहे हों, लेकिन ये आपके ही लोग हैं जो यह (मुस्लिम विरोधी) तमाशा कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि वे गलत हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे." ओवैसी से भागवत की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों का 'डीएनए' एक है और हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए.

भागवत ने यह बयान देश की स्वतंत्रता से पहले की, मुगल-काल की या उससे भी पहले की मस्जिदों को लेकर उपजे विवादों को लेकर दिया था. कुछ हिंदुओं का मानना है कि ये मस्जिदें, मंदिरों को नष्ट करके बनाई गई थीं. हैदराबाद से पांच बार के सांसद और संसद में अपनी पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि ओवैसी ने कहा, 'क्या ये सभी लोग जो अदालतों में जा रहे हैं और वाद दायर कर रहे हैं मोहन भागवत के समर्थक नहीं हैं?' तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा में एआईएमआईएम के सात विधायक हैं.राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी छोटी भूमिका के बावजूद, ओवैसी मुस्लिम अधिकारों को लेकर आवाज उठाने की वजह से देश भर में मुसलमानों के लिए एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं. आरएसएस और भाजपा का विरोध और विपक्षी दलों की भी मुखर आलोचना करने की वजह से मुसलमानों के बीच उनकी अपील बढ़ी है.

जीरो टैरिफ के अपने बयान से पलटे ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ हटाने की पेशकश की है, लेकिन वो इस दावे से पलट गए और कहा कि स्पष्ट सफलता के बावजूद वे व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने की जल्दी में नहीं हैं.

डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि भारत ने कहा कि चल रही बातचीत जटिल है और अंतिम रूप से बहुत दूर है. फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ऐसे देश का टॉप एग्जांपल है, जहां बाधाएं हैं, जिन्हें वह खत्म करने के लिए संकल्पित हैं. उन्होंने कहा, "वे व्यापार करना लगभग असंभव बना देते हैं. क्या आप जानते हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपने टैरिफ में 100% कटौती करने को तैयार हैं?" लेकिन ट्रंप ने इस बात पर भी मिक्स सिग्नल दिए कि सौदा कितना करीब हो सकता है, उन्होंने कहा, "यह जल्द ही होगा. मुझे कोई जल्दी नहीं है.

बीजेपी नेताओं को बोलने की मिलेगी ट्रेनिंग, जून में लगेगा प्रशिक्षण शिविर

भोपाल। पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के बयानों और कृत्यों से परेशान बीजेपी अब जल्द ही अपने नेताओं को बोलने की ट्रेनिंग देने वाली है. इसमें उन्हें बीजेपी की रीति-नीति के बारे में बताया जाएगा, साथ ही यह भी सिखाया जाएगा कि उन्हें कब, क्या और कैसे बोलना है ताकि वे विवादित बयान देने से बच सकें. जून महीने में यह ट्रेनिंग कैंप भोपाल से बाहर किसी शांत जगह पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी मंत्रियों, विधायकों और अन्य नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर बयान देने और किन मुद्दों पर नहीं बोलना है, इस बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा.

इस प्रशिक्षण शिविर में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया व कम्युनिकेशन विशेषज्ञ अलग-अलग सत्रों में नेताओं का मार्गदर्शन करेंगे. वे उन्हें पार्टी अनुशासन में रहने और पार्टी व उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव से बचने के तरीके बताएंगे. बता दें कि हाल ही में बीजेपी नेताओं के कृत्यों और बयानों से पार्टी की काफी किरकिरी हुई है. हाल ही में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी. इसके बाद उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में विवादित बयान दिया और फिर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया. करीब तीन सप्ताह पहले ग्वालियर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी एक होटल छापे के दौरान विवादों में घिर गए थे. इसके अलावा, पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या सागर जिले में बीजेपी नेताओं की आपसी बयानबाजी का मामला, इन सब से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है।

गाजा के 10 लाख लोगों को लीबिया में बसाया जाएगा!

गाजा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के लिए बड़ी योजना तैयार की है, जिस पर उनका प्रशासन तेजी से काम कर रहा है. एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी के करीब 10 लाख लोगों को लीबिया में स्थायी रूप से पुनर्वास की योजना पर विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट में इस योजना की जानकारी रखने वाले पांच अलग-अलग सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने इस प्रस्ताव को इतनी गंभीरता से लिया कि इसे लीबिया के नेतृत्व के सामने भी रखा गया. इयह बातचीत कूटनीतिक स्तर पर हो चुकी है. इस योजना के तहत अगर लीबिया गाजा के फिलिस्तीनियों को बसाने को तैयार होता है तो अमेरिका उसे अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा. यह वह फंड है, जिसे वाशिंगटन ने एक दशक पहले रोक दिया था और अब दोबारा जारी करने की पेशकश है।

भारत के पास होगी रोबोटिक सेना... DRDO बना रहा लड़ाके रोबोट

डीआरडीओ के वैज्ञानिक सैन्य मिशनों के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रहे हैं, जो जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. यह रोबोट जटिल कार्य, स्वायत्त नेविगेशन और खतरनाक सामग्रियों को संभालने में सक्षम होगा. उन्नत सेंसर, एक्ट्यूएटर्स और नियंत्रण प्रणाली से लैस, यह 2027 तक तैयार होगा जो रक्षा और अन्य क्षेत्रों में क्रांति लाएगा. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिक एक ऐसे मानवरोबोट (ह्यूमनॉइड रोबोट) के विकास पर काम कर रहे हैं, जो अग्रिम पंक्ति के सैन्य मिशनों में हिस्सा ले सके. एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस रोबोट का उद्देश्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना जटिल कार्यों को अंजाम देना है. डीआरडीओ के तहत एक प्रमुख प्रयोगशाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (इंजीनियर्स), इस मशीन को विकसित कर रही है.

चार साल से चल रहा है प्रोजेक्ट

पुणे में सेंटर फॉर सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एडवांस्ड रोबोटिक्स के समूह निदेशक एस.ई. तलोले ने बताया कि उनकी टीम पिछले चार साल से इस परियोजना पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हमने ऊपरी और निचले शरीर के लिए अलग-अलग प्रोटोटाइप विकसित किए हैं. आंतरिक परीक्षणों के दौरान कुछ कार्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है. यह ह्यूमनॉइड रोबोट जंगल जैसे कठिन इलाकों में भी काम कर सकेगा. हाल ही में पुणे में आयोजित नेशनल वर्कशॉप ऑन एडवांस्ड लेग्ड रोबोटिक्स में इस रोबोट को प्रदर्शित किया गया था.

उन्नत विकास चरण में प्रोजेक्ट

वर्तमान में यह प्रोजेक्ट अपने उन्नत विकास चरण में है. टीम का ध्यान रोबोट की ऑपरेटर के निर्देशों को समझने और उन्हें लागू करने की क्षमता को और बेहतर बनाने पर है. इस प्रणाली में तीन मुख्य घटक शामिल हैं:

एक्ट्यूएटर्स: ये मानव मांसपेशियों की तरह गति उत्पन्न करते हैं.

सेंसर: ये आसपास के वातावरण से वास्तविक समय में डेटा एकत्र करते हैं.

नियंत्रण प्रणाली: ये एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करके रोबोट के कार्यों को निर्देशित करती हैं.

तलोले ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि रोबोट वांछित कार्यों को सुचारू रूप से कर सके. इसके लिए संतुलन, तीव्र डेटा प्रोसेसिंग और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में महारत हासिल करना आवश्यक है. डिज़ाइन टीम का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक किरण अकेला ने बताया कि शोधकर्ता इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. 2027 तक इस परियोजना को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

राहुल पर भारी पड़ा सुदर्शन का शतक

१० विकेट से जीती गुजरात, प्लेऑफ में बनाई जगह

नई दिल्ली। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को उसी के घर पर 10 विकेट से रौंद डाला है. इस मैच में दिल्ली ने पहले खेलते हुए 199 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जवाब में गुजरात ने बिना कोई विकेट गंवाए इस मैच को 19 ओवर में ही अपनी झोली में डाल लिया है. इसी के साथ गुजरात आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. दिल्ली के गेंदबाज गुजरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को आउट ही नहीं कर पाए. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य मिला था. गुजरात के टॉप ऑर्डर ने ऐसा धमाल मचाया कि दिल्ली के गेंदबाज, GT की ओपनिंग जोड़ी को ही नहीं भेद पाए. एक तरफ साई सुदर्शन ने 61 गेंद में 108 रन की शानदार पारी खेली, दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल भी नाबाद 93 रन बनाकर लौटे.

गिल और सुदर्शन ने मिलकर 15 चौके और 11 छक्के लगाए. दिल्ली जब पहले बैटिंग करने उतरी तो उसके लिए केएल राहुल ने 65 गेंदों में 112 रनों की नाबाद पारी खेल महफिल लूटी थी. इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए. एक गजब की बात यह रही कि इस पूरे मैच में 39 ओवर फेंके गए, कुल 404 रन बने लेकिन केवल 3 विकेट ही गिरे.

IPL 2025 प्लेऑफ में पहुंची गुजरात

गुजरात टाइटंस IPL 2025 के प्लेऑफ में जाने वाली पहली टीम बन गई है. गुजरात के अब 12 मैचों में 18 अंक हो गए हैं, उसके अभी 2 मैच बाकी हैं जिससे वह 22 अंकों तक पहुंच सकती है. गुजरात के पास टेबल टॉपर बनने का सुनहरा मौका है. अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के 17-17 अंक हैं. जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है, GT के खिलाफ हार के बावजूद वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर नहीं हुई है।

पंजाब ने राजस्थान को 10 रन से हराया

जयपुर। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हरा दिया है. इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने पहले खेलते हुए स्कोर बोर्ड पर 219 रन लगाए थे, इसके जवाब में राजस्थान निर्धारित 20 ओवरों में 209 रन ही बना पाई. इस मैच को जीतकर पंजाब ने प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. पंजाब की जीत में सबसे बड़ा योगदान नेहाल वाढेरा और हरप्रीत बराड का रहा. वाढेरा ने 70 रन और हरप्रीत ने 3 अहम विकेट लिए.

जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को 220 रनों का लक्ष्य मिला था. जवाब में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई. दोनों ने मिलकर 5वें ओवर में ही टीम का स्कोर 60 रन से पार पहुंचा दिया था. इस बीच सूर्यवंशी 15 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो गए. यशस्वी जायसवाल ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन फिफ्टी पूरी करते ही आउट हो गए. जायसवाल ने 9 चौके और 1 छक्के से सुसज्जित अपनी पारी में 25 गेंद खेलकर 50 रन बनाए.संजू सैमसन ने इस मैच में रिटर्न किया, लेकिन वो सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए. रियान पराग से टीम को एक बड़ी पारी की जरूरत थी, उन्हें 13 रन के स्कोर पर हरप्रीत बराड ने क्लीन बोल्ड कर दिया. बड़ी पार्टनरशिप ना होना राजस्थान की मुश्किलें बढ़ा रहा था.ध्रुव जुरेल किसी आयरन मैन की तरह एक छोर संभाले हुए थे।

केकेआर को मिला एक और मिस्ट्री स्पिनर

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 18 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, अब हर एक मुकाबला प्लेऑफ के लिए

महत्वपूर्ण है. शनिवार को RCB बनाम KKR मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जिसने डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने के सपने को तोड़ दिया. अब केकेआर फ्रेंचाइजी ने शिवम शुक्ला को अपनी टीम में शामिल किया है. 29 वर्षीय शिवम शुक्ला वेस्टइंडीज प्लेयर रोमन पॉवेल के टेम्परारी रिप्लेसमेंट हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को इसकी घोषणा की. 8 मई को आईपीएल रद्द होने के बाद पॉवेल स्वदेश लौट गए थे. 17 मई से इसकी फिर से शुरुआत हो गई है, लेकिन चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने भारत लौटने से इनकार कर दिया. शिवम ने कुल 8 टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने कुल 180 गेंदें डाली हैं, जिसमें 189 रन खर्चे हैं और 8 विकेट चटकाए हैं. टी20 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 29 रन देकर 4 विकेट लेने का है. उनकी इकॉनमी 6.30 की रही है, जो इस फॉर्मेट में अच्छी कही जा सकती है.

IPL 2025 के बाद एक और सीजन खेलेंगे एमएस धोनी?

नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL 2025 किसी बुरे सपने की तरह रहा, जिसे फ्रेंचाइजी और फैंस भुला देना चाहेंगे. इस बीच एमएस धोनी को लेकर एक खबर आई है, जो टीम और उनके प्रशंसकों को खुश कर देगी. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL 2025 किसी बुरे सपने की तरह रहा. पांच बार की चैंपियन सीएसके इस सीजन प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बनी. ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद एमएस धोनी को एक बार फिर कमान संभालनी पड़ी लेकिन वह भी सीएसके की किस्मत को नहीं बदल सके. पिछले मैच में जीतन दर्ज करने से पहले सीएसके ने धोनी की कप्तानी में लगातार 4 मैच हारे थे. इसके बाद कहा जा रहा था कि एमएस धोनी इस सीजन के बाद आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो सीएसके और धोनी के फैंस को खुश कर देगी. चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रैंचाइज़ के सूत्रों को भरोसा है कि धोनी IPL 2025 के बाद भी खेलते रहेंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीम में बहुत सी कमियां हैं, जिन्हें दूर रखना मुश्किल है, इसलिए इस समय एमएस धोनी को टीम से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता.अपने खराब दौर से गुजर रही चेन्नई एक बार फिर बदलाव के दौर से गुजर रही है. IPL 2025 में अभी तक खेले 12 में से सीएसके 9 मैच हार चुकी है, इसमें लगातार 5 मैच और फिर लगातार 4 मैच हारना शामिल है. जो कि IPL के इतिहास में उनका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है. इसने CSK के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें सीज़न के दौरान चोटिल होने वाले खिलाड़ियों की जगह कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

सिर्फ धोनी के फैंस असली, बाकी सब खरीदे हुएः भज्जी

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने नए बयान से सनसनी फैला दी है. उन्होंने कहा है कि सिर्फ एमएस धोनी के पास असली फैंस हैं, जबकि अन्य क्रिकेटरों ने फैन पैसे से खरीदे हैं. उन्होंने यह बयान 17 मई को बारिश के कारण रद्द हुए RCB vs KKR मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए दिया. हरभजन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि धोनी ने अपने भविष्य को लेकर CSK मैनेजमेंट को जानकारी दे दी है कि उनका IPL 2025 के बाद रिटायर होने का कोई मन नहीं है. कमेंट्री करते समय हरभजन सिंह ने एमएस धोनी से आग्रह किया कि उन्हें जब तक खेलते रहना चाहिए जब तक उनका मन करे. उनके बयान से लोग तरह-तरह की बातें बनाने लगे हैं कि शायद हरभजन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों पर तंज कसा है. हरभजन सिंह ने कहा, "कितना बचा हुआ है और जब तक दम है खेलो भाई. मेरी टीम होती तो मैं शायद कुछ और फैसला लेता।

बंद हो सकते हैं वोडाफोन आईडिया

नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (VIL) आर्थिक परेशानियों से घिरी हुई है और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है. कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को बताया है अगर सरकार ने वक्त रहते बकाए AGR (Adjusted Gross Revenue) पर मदद नहीं की, मार्च 2026 के बाद भारत में कंपनी का कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा.

कंपनी को मजबूरन जाना पड़ सकता है NCLT

कर्ज में डूबी कंपनी ने सरकार को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि अगर सरकार ने मदद नहीं की, तो उसे दिवालियापन कार्यवाही के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal - NCLT) का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. 17 अप्रैल 2025 को VIL के सीईओ अक्षय मूंदड़ा ने DoT सचिव को लिखी चिट्ठी में कंपनी ने सरकार से मदद की मांग की. कंपनी ने यह भी दावा किया है कि 26,000 करोड़ रुपये के इक्विटी इन्फ्यूजन और और सरकार के बकाये को इक्विटी में बदलने के बावजूद आर्थिक तंगी की मार झेल रही कंपनी को बैंकों से कोई मदद नहीं मिली है. बता दें कि VIL में अभी सबसे अधिक 49 परसेंट की हिस्सेदारी सरकार के पास है. कंपनी के बकाये को इक्विटी में बदलने के बाद यह हिस्सा सरकार को मिला है.

सरकार से मदद की है जरूरत

DoT सचिव को लिखी चिट्ठी में कंपनी ने कहा कि AGR मामले में अगर सरकार ने तुरंत मदद नहीं की, तो बैंक फंडिंग की बात आगे नहीं बढ़ेगी और बैंक कंपनी को लोन नहीं देंगे. कंपनी का कामकाज ठप्प हो जाएगा. कंपनी ने यह भी कहा कि अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो न केवल कंपनी की सेवाएं थोड़े समय के लिए बाधित होगी, बल्कि सरकार की इसमें 49 परसेंट की हिस्सेदारी का मूल्य भी शून्य तक गिर सकता है. इसके चलते कंपनी से स्पेक्ट्रम बिक्री के 1.18 लाख करोड़ रुपये बकाए की वसूली नहीं हो पाएगी. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कंपनी ने AGR बकाए पर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की छूट की मांग की है. इस याचिका पर 19 मई को सुनवाई होने की संभावना है. बता दें कि सरकार के स्पेक्ट्रम और एजीआर बकाया के एक हिस्से को इक्विटी में बदलने करने के बाद भी वोडाफोन आइडिया पर अभी भी 1.95 लाख करोड़ रुपये बकाया है।

'मेड इन इंडिया' का डंका, स्मार्टफोन बना भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट

नई दिल्ली। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत के आंकड़े चौंकानेवाले हैं. वित्त वर्ष 2025 (वित्त वर्ष 2024-2025) में भारत से 24.14 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए. यह पिछले साल हुए 15.57 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट से 55 परसेंट ज्यादा है. हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इनमें से ज्यादातर स्मार्टफोन अमेरिका, नीदरलैंड, इटली, जापान और चेक गणराज्य को भेजे गए.

अकेले अमेरिका में हुआ इतने का एक्सपोर्ट

वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत ने अकेले अमेरिका को 10.6 बिलियन डॉलर का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया. यह एक साल पहले अमेरिका को एक्सपोर्ट किए गए 5.57 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन से दोगुना है. भारत से स्मार्टफोन निर्यात ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और हीरे के एक्सपोर्ट को पछाड़ दिया है. यानी कि भारत अब पेट्रोकेमिकल्स और हीरे से ज्यादा स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट करता है. अमेरिका के अलावा, नीदरलैंड ने पिछले वित्त वर्ष में 2.2 बिलियन डॉलर के iPhone भारत से इम्पोर्ट किए. इसी तरह से इटली में 1.26 बिलियन डॉलर और चेक रिपब्लिक में 1.17 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन भेजे गए. वित्त वर्ष 2025 में टोक्यो के लिए भी स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर 520 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-2023 में यह मात्र 120 मिलियन डॉलर था. पिछले दो वित्तीय वर्षों में सरकार के प्रयासों के चलते स्मार्टफोन के निर्यात में उछाल आया, जिसमें उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम भी शामिल है. देश में स्मार्टफोन की कई यूनिट्स भी खुली हैं. इसके चलते इस सेक्टर में भारत का सप्लाई चेन मजबूत हो रहा है, अधिक निवेश आकर्षित हो रहा है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

कांग्रेस का आरोप; स्काईवॉक भाजपा के भ्रष्टाचार की निशानी

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने 15 वर्ष शासन काल में जिस प्रकार से शासकीय धन का दुर्विनियोजन किया, भ्रष्टाचार किया उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण स्काईवॉक प्रोजेक्ट है जो दिन प्रतिदिन रायपुर की जनता को उनके साथ हुये विश्वघात, उपेक्षा और धोखाधड़ी की याद दिलाता है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत कितनी भी गलत बयानी कर ले रायपुर का एक्सप्रेस-वे, स्काईवॉक भाजपा के भ्रष्टाचार का स्मारक के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है। तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत बिना किसी आवश्यकता के रायपुर शहर में एक स्काई वॉक बनाने का प्रोजेक्ट अपने रसूख का प्रयोग करके पास करवाए थे। इसका कोई औचित्य या आवश्यकता ही नहीं थी। जनता द्वारा भी स्काई वॉक निर्माण के प्रोजेक्ट को लेकर तत्कालीन सरकार का विरोध किया था। श्री मूणत के मंसूबों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। उक्त प्रोजेक्ट तत्कालीन भाजपा सरकार और लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे श्री राजेश मूणत के भ्रष्टाचार के जीते जागते उदाहरण के रूप में रायपुर में मौजूद है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार अधूरे स्काईवॉक पर पैसा खर्च करने के बजाय आम जनता की मांग के अनुरूप फ्लाई ओवर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। जिसे वर्तमान एवं भविष्य में भी यातायात समस्या

का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्काईवॉक योजना के खिलाफ शहर की जनता बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी, डॉक्टर सभी वर्ग थे। आज सरकार ने अधूरे स्काईवॉक को पुनः बनाने का फैसला किया है इसके खिलाफ ही आम जनता की प्रतिक्रिया आ रही है। सरकार को स्काईवॉक को बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और शहर के भविष्य के मांग के अनुरूप फ्लाई ओवर बनाने पर योजना बनानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अब एक बार फिर भ्रष्टाचार की इस इमारत को पूरा करने के लिए 37 करोड़ से अधिक राशि खर्चा किया जाना जनता के पैसे की बर्बादी है। एक आदमी के जिद और अहंकार की संतुष्टि के लिए फिजूल का निर्माण कार्य कराया जा रहा। भाजपा के समय स्काईवॉक का जो ठेका हुआ था उससे ही पता चलता है कि इसके टेंडर प्रक्रिया में पूरी तरह अनियमितता बरती गई थी।

कांग्रेसी आरोप और स्काईवाक पर मूणत का पलटवार

मूणत ने कहा- पूर्व CM भूपेश बघेल को मुझसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हैं। इस वजह से उन्होंने इस काम को रोका और विरोध किया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए लेकिन खुद कांग्रेस सरकार की बनाई हुई कमेटियों ने बताया कि स्कायवॉक उपयोगी है। EOW ने क्लीनचिट दी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। शास्त्री चौक से लेकर जयस्तंभ चौक और दूसरी तरफ जेल चौराहे तक हैवी ट्रैफिक होता है। कई दुर्घटनाएं हुईं। यहां ट्रैफिक मैनेजमेंट पर स्टडी की गई। 2016 में सर्वे हुआ तो पता चला यहां हर रोज 25 हजार लोग चल रहे हैं। फ्लाईओवर बनाने का सुझाव आया लेकिन शहर दो हिस्सों में बंट जाता इसलिए पैदल आबादी के लिए स्कायवॉक बनाना तय हुआ। कैसे बनेगा, डिजाइन क्या होगा, इसे लेकर तीन प्रेजेंटेशन रायपुर में हुए। तब की महापौर डॉक्टर किरणमई नायक, ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा, नगर निगम में सभापति रहे प्रमोद दुबे भी थे। कुछ गड़बड़ी थी तो कांग्रेस की 5 साल सरकार थी, भूपेश बघेल को इसे तोड़ने का निर्देश दे देना चाहिए था न, किसने रोका था। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या कांग्रेस बता दें कि कोई एक काम रायपुर की जनता के लिए किया हो तो।

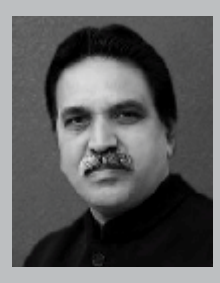

कांग्रेस नेता नागेश बोले- प्रॉपर्टी के पेपर ले गई EOW टीम

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में कांग्रेस नेता जी नागेश और ठेकेदार कमलेश नाहटा के घर टीम ने सुबह दबिश दी थी। देवेंद्र नगर में कांग्रेसी पार्षद उम्मीदवार श्रीनिवास राव के घर पहुंची। श्रीनिवास के साथ उनके भाई जी नागेश रहते हैं। नागेश कवासी के करीबी माने जाते हैं। वहीं इस शराब घोटाले में EOW को आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मिल गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ACB-EOW की टीम ने कवासी लखमा और उनके करीबियों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। शनिवार को रायपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर और अंबिकापुर में दबिश देकर दस्तावेज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कई बैंक अकाउंट और जमीनों में निवेश से संबंधित दस्तावेज और 19 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं।

जी नागेश के भाई जी श्रीनिवास राव ने बताया कि सुबह करीब 5:45 बजे टीम घर पहुंची थी। छोटे भाई ने घर का दरवाजा खोला। EOW के अधिकारियों ने बताया कि नागेश के नाम पर सर्च वारंट है। हमने अधिकारियों को घर में सम्मान से

बैठाया। श्रीनिवास ने कहा कि हम कहीं से गलत नहीं है, इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं है। EOW के अधिकारियों को हमने जांच में पूरा सहयोग किया। जी श्रीनिवास राव ने बताया कि अधिकारियों ने कहा कि आप कवासी लखमा के करीबी हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि आबकारी मामले में आपकी संलिप्तता है? लेकिन हमने उन्हें जानकारी दी है कि उनसे हमारा व्यापारिक संबंध नहीं है। लेकिन पूर्व मंत्री लखमा से हमारा व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध है।

इनके घर पर पड़ा छापा

- रायपुर कांग्रेसी नेता जी नागेश, ठेकेदार कमलेश नाहटा।
- जगदलपुर : कंप्यूटर कारोबारी प्रेम मिगलानी।
- दंतेवाड़ा : कांग्रेसी नेता राजकुमार तामो।
- सुकमा : योग आयोग के पूर्व सदस्य राजेश नारा, हार्डवेयर कारोबारी अनीश बोथरा, पेट्रोल पंप संचालक जयदीप भदौरिया, पूर्व मंत्री लखमा के ड्राइवर शेख बशीर और बशीर अहमद

संत कबीर के विचार और वाणी में तेज, इसलिए देश में बढ़ा कबीर क्रेज

शहर सत्ता/रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के सेलूद स्थित सद्गुरु कबीर

आश्रम में आयोजित दो दिवसीय संत समागम समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री साव ने संतों से आशीर्वाद लिया। श्री साव श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए संत कबीर के आदर्शों व शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि, संत समाज के मार्गदर्शक होते हैं, संत दूसरे के लिए जीते हैं। आश्रम में संत कबीर को मानने वाले संतों का समागम हुआ है।

संत कबीर ने दुनिया के सामने विचार रखा। किस प्रकार से आचार और व्यवहार करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि, कबीर साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके उपदेश जात-पात, अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध एक जन जागृति का काम कर रहे हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के लिए संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि, आज संत कबीर के विचारों को घर-घर तक पहुंचाने का काम करना है।

कवर्धा में धर्मांतरण को लेकर बवाल

शहर सत्ता/ कवर्धा/ रायपुर। कवर्धा जिले में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आदर्श नगर क्षेत्र के एक घर में बंद कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी और वहां कई अलग-अलग धर्म और मिशनरी समर्थक के लोग मौजूद थे। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पहुंची थी। इसकी जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं वहां पहुंच गए। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। विहिप कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए और हंगामा किया। उनका आरोप है कि फादर थॉमस और उनकी पत्नी यहां गुप्त रूप से धर्मांतरण करा रहे थे। जब वे विरोध करने लगे तो मिशनरियों से झूमाझटकी की स्थिति बन गई।

अंदर कमरे में हुई घटना का वीडियो भी सामने आया है। यहां बड़ी संख्या में लोग दिखे। साथ ही बाइबिल भी रखी हुई थी। VHP

हिंदू संगठन का आरोप; बीमारी ठीक करने का दे रहे थे कमरे में 20 से ज्यादा लोगों को झांसा

कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिंदुओं को कैंसर ठीक करने, जादू टोना भगाने जैसे झांसे में लेकर ब्रेन वॉश कर रहे थे। हिंदू जागरण मंच के सदस्य सौरभ सिंह ने कहा कि फादर थॉमस, होली किंगडम स्कूल का प्रिंसिपल है। उस पर पहले भी स्कूल में बच्चों का जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप लग चुके हैं। एक मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फीस माफ करने के नाम वे धर्मांतरण करा रहे हैं।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

सौरभ सिहं ने कहा कि जब हमारी टीम पहुंची तो बचने के लिए वे लोग महिलाओं को आगे कर रहे थे तो झूमाझटकी हो गई। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए और धर्मांतरण की घटनाओं की गंभीरता से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा- केंद्र की अधिनायकवादी मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

भाजपा सरकार को चेतावनी देने 19 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली

शहर सत्ता/रायपुर। सोमवार 19 मई को जांजगीर-चांपा में आयोजित कांग्रेस की राज्य स्तरीय 'संविधान बचाओ रैली' निकलेगी। इस रैली में एआईसीसी के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, एआईसीसी के महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रभारी सचिवगण एस. सम्पत, जरिता लैतफलांग, विजय जांगिड़, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस.सिंहदेव सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र की अधिनायकवादी मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार कर दिया है। देश के संसाधनों पर अपने पूंजीपति मित्रों का एकाधिकार बनाने लगातार जन विरोधी निर्णय थोपे जा रहे हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेसजन हर स्तर पर लड़ाई लड़ रहे है। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार का यू टर्न नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संघर्ष की जीत है, सामाजिक न्याय को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जातीय जनगणना कराने के लिए यू-टर्न लिया है। दीपक बैज ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जनसरोकार के प्रमुख तीन मांगों को लेकर जनता के बीच

जाएगी और केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाएगी। पहला आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीलिंग हटाने की मांग, इसके लिए। एआईसीसी ने अहमदाबाद की बैठक में प्रस्ताव भी पास किया है। दुसरा केंद्र की सरकार ने नेशनल बजट के एलोकेशन में एस, एसटी के लिए बजट दुर्भावना पूर्वक कम किया जा रहा है, उसे बढ़ाया जाए और पॉपुलेशन के आधार पर बजट होसभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी युवाओं को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाए। 2006 में यूपीए की सरकार ने संविधान के आर्टिकल 15(5) में इसका प्रावधान भी किया है, इसका सरकारी स्कूलों में तो लाभ मिल रहा है, लेकिन निजी संस्थान में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।

रैली में शिरकत करने पहुंचे पायलट : प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रविवार को शाम साढ़े 5 बजे नियमित विमानसेवा से राजधानी रायपुर पहुंचे। शाम 6ः00 बजे समता कालोनी में पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत हुये कारोबारी स्व.दिनेश मीरानिया के परिवार से मुलाकात किये। शाम 6ः30 बजे रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे एवं रात्रि विश्राम बिलासपुर में करेंगे। कल 19 मई सोमवार को दोपहर 2 बजे बिलासपुर से जांजगीर-चांपा के लिये रवाना होंगे।

सांसद, विधायकों और अफसरों ने किया सेना के पराक्रम को नमन

नगरीय निकायों तथा गांव-गांव में निकली तिरंगा यात्रा, गूंजे "भारत माता की जय", "जय जवान", और "वंदे मातरम" के नारे

शहर सत्ता/रायपुर। तिरंगा यात्रा के दौरान जिले के नगरीय निकायों और गांव-गांव में "भारत माता की जय", "जय जवान", और "वंदे मातरम" जैसे गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। हर तरफ देशभक्ति का जोश और उत्साह देखने को मिला। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे सम्मान और गर्व के साथ यात्रा में भाग लिया। पंडरभट्ठा और खरोरा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की रणनीतिक दृढ़ता के सम्मान में आयोजित की गई थी। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष के साथ राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन किया।

जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम गनोद में विशेष रूप से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक गुरु खुशवंत साहेब और विधायक इंद्रकुमार साहू ने नेतृत्व किया। गांव के लोगों ने भारी संख्या में भाग लेकर यह दर्शाया कि देश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे जवानों के प्रति उनका गहरा सम्मान और प्रेम है। लोग तिरंगा थामे, पारंपरिक वेशभूषा में देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में चल रहे थे, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया।

इस मौके पर विधायक मोतीलाल साहू, विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा सहित कई अन्य अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन यात्रा में शामिल हुए और वीर सैनिकों को नमन किया। तिरंगा यात्रा केवल गणोद तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिले के अन्य कई स्थानों पर भी जोश और उत्साह के साथ इसका आयोजन किया गया। गोबरा नवापारा, माना नगर पालिका, ग्राम पंचायत दोंदेकला, नगर पालिका आरंग, बिरगांव नगर निगम, नगर पंचायत समोदा और नगर पालिका अभनपुर जैसे स्थानों पर भी नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर इस यात्रा को सफल बनाया।

मंत्री देवांगन ने कोरबा को दी 1.20 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गांव एवं शहरी क्षेत्रों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन रविवार 18 मई को अपरान्ह 5.30 बजे कोरबा में 1.20 करोड़ रूपए से अधिक निर्माण कार्या के लोकार्पण एवं का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री देवांगन दोपहर 12.15 बजे नगर निगम प्रशासन द्वारा आयाजित ई-रिक्शा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। तत्पश्चात 3.20 बजे आशीर्वाद प्वाइंट टी.पी नगर में वीरांगना रानी अहिल्या बाई होल्कर की 300 वी जयंती 31 मई को मनाने के संबंध में कार्यशाला कार्यक्रम में शामिल हुए। निर्धारित दौरा के अनुसार मंत्री श्री देवांगन शाम 5.30 बजे नगर निगम कोरबा के कटहल गार्डन एम.पी नगर में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 25 में कटहल गार्डन एम.पी नगर से मेन रोड तक एण्ड टू एण्ड पेविंग कार्य स्वीकृत राशि 21 लाख रूपए एवं 55 लाख रूपए के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य का लोकार्पण करेंगे। दौरा कार्यक्रम के अनुसार श्री देवांगन शाम 6.20 बजे चंद्रा समाज सामुदायिक भवन पोड़ीबहार में विभिन्न निर्माण कार्यो के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें वार्ड क्रमांक 31 के निर्मला स्कूल के पास वेडिंग जोन का निर्माण कार्य स्वीकृत राशि 19.65 लाख रूपए, वार्ड क्रमांक 22 में चंद्रा समाज के भवन के पास निर्मित सामुदायिक भवन के ऊपर हॉल निर्माण के 25 लाख रूपए शामिल है।

सांसद बृजमोहन ने कहा- गांव से शहरों तक दिख रहा है सुशासन

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आज आरंग ब्लॉक के ग्राम पंडरभट्ठा और ग्राम खरोरा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनता को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, समाधान अब गांव में ही हो रहा है। समाधान शिविर के अंतर्गत 300 से अधिक युवाओं को लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया गया। शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाणपत्र एवं सामग्री किट वितरित की गई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ग्रामीणों में टीबी, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का पता चला, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप यदु, जनपद अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला, उपाध्यक्ष दिनेश खूंटे सहित अनेक जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 1 जून को भोंगापाल में बौद्ध महोत्सव का होगा महाआयोजन

भोंगापाल में बनेगा 'युद्ध नहीं बुद्ध' की थीम पर बौद्ध शांति पार्क

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में आगामी 1 जून 2025 को बस्तर संभाग के कोंडागांव नारायणपुर जिले अंतर्गत आने वाले भोंगापाल में राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का गरिमामय आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ बस्तर में युद्ध नहीं बुद्ध की शांति के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दृष्टिगत रखते हुए बौद्ध महोत्सव के इस राज्य स्तरीय आयोजन में भोंगापाल और इसके आसपास के विशाल चिन्हांकित परिक्षेत्र में अद्भुत, अद्वितीय और अनुपम बौद्ध शांति पार्क निर्माण करने की भी पहल की जाएगी।

इस संदर्भ में केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम की उपस्थिति में गत दिनों रायपुर में डॉ.अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। मुख्यमंत्री द्वारा भोंगापाल बौद्ध महोत्सव में शामिल होने की मिली सहमति के पश्चात 1 जून को भोंगापाल में यह आयोजन गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित करने आज अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भोंगापाल बौद्ध महोत्सव के आयोजन में अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी शासन प्रशासन को हर संभव सहयोग देगा। ए.डब्लू.एस. प्रबंधकारिणी की आज शनिवार को हुई बैठक मे लिए गए फैसले के अनुरूप भोंगापाल बौद्ध महोत्सव के आयोजन की रूपरेखा और कार्ययोजना पर भी गंभीरता से विचार किया गया। बताया गया कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक संभाग और जिलों के सभी समाज के लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सर्व समाज के लोगों और संगठनों के समन्वय से आयोजित किए जाने वाले इस राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव हेतु व्यापक तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में महासमुंद जिले के सिरपुर में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध स्थल अपनी पूरी ऐतिहासिकता और समृद्ध पुरातात्विक विरासत के साथ मौजूद है। इसी प्रकार बस्तर अंचल में पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व का स्थल कोंडागांव जिले के भोंगापाल और इसके आसपास भी प्रचुरता के साथ है।

छत्तीसगढ़ के कामयाब टॉकीज संचालकों में शुमार शख्सियत लक्की की नजर में यह है सिनेमा

"सिनेमा" मतलब 'सीने में मां'

- **लकी रंगशाही ने बताया छत्तीसगढ़ी फिल्मों का बदलता परिदृश्य और सिंगल स्क्रीन का भविष्य**

शहरसात्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग में गहरी पैठ रखने वाले लकी रंगशाही का मानना है कि सिनेमा उनके लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि भावना है "सिनेमा मेरे लिए सीने में मां जैसा है।" उनका बचपन रायपुर के दो प्रमुख सिनेमा घर—जयराम और सम्राट—के माहौल में बीता, जिनका संचालन उनके पिता स्वर्गीय सत्येंद्र रंगशाही किया करते थे। लकी रंगशाही ने 19 वर्ष की उम्र में ही फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कदम रख दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सब-डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य शुरू किया। वर्तमान में वह न केवल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बल्कि सिनेमा टॉकीज़ का एग्जीबिशन (प्रदर्शन) भी करते हैं।

क्षेत्रीय सिनेमा की बढ़ती ताकत

उनका मानना है कि दर्शकों की क्षेत्रीय फिल्मों में रुचि घटी नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ी है। बशर्ते कंटेंट दमदार हो। "आज के दर्शक वही फिल्में देखना चाहते हैं जो उनके मन को छू जाएं और मनोरंजन दें। जब छत्तीसगढ़ी फिल्में अच्छी बनती हैं, तो सिंगल स्क्रीन थिएटरों में भी भीड़ उमड़ती है।" लकी का कहना है कि हिंदी और हॉलीवुड फिल्मों का दर्शक वर्ग अब मल्टीप्लेक्स की ओर शिफ्ट हो गया है, ऐसे में अच्छी क्षेत्रीय फिल्में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म मेकर बॉक्स ऑफिस पर खुद को साबित कर चुका हो, तो उसे स्क्रीन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती।

थिएटर मालिकों की भूमिका और सरकारी उदासीनता

छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रचार-प्रसार को लेकर लकी कहते हैं कि थिएटर मालिक बिना किसी शुल्क के अपने सिनेमा घरों में पोस्टर लगाते हैं और ट्रेलर चलवाते हैं। साथ ही यूट्यूबर्स को प्रमोशनल गतिविधियों के लिए सिनेमा परिसर में जगह भी देते हैं। "आज सोशल मीडिया प्रचार का जमाना है, और हम उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं," उन्होंने कहा। हालांकि, लकी ने अफसोस जताया कि राज्य सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ी फिल्मों या सिंगल स्क्रीन थिएटरों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। उन्होंने सरकार से बिजली दरों में विशेष छूट देने की मांग की, जिससे सिनेमाघरों को राहत मिल सके।

बदलते टिकट रेट और फिल्म निर्माण का समीकरण

लकी रंगशाही के अनुसार, मौजूदा टिकट दरें संतुलित हैं। लेकिन यदि इन्हें और घटाया गया, तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि फिल्मों का बजट अब काफी बढ़ चुका है। उन्होंने साफ कहा कि "अगर फिल्म अच्छी और एंटरटेनमेंट से भरपूर हो, तो टिकट रेट मायने नहीं रखते—दर्शक थिएटर तक जरूर आते हैं।"

छत्तीसगढ़ी सिनेमा की गुणवत्ता और बाजार

लकी ने छत्तीसगढ़ी फिल्मों की तुलना भोजपुरी फिल्मों से करते हुए कहा कि "आज हमारे यहां उनसे बेहतर कंटेंट बन रहा है। निर्माता-निर्देशक टेक्निकली बेहतर और आकर्षक फिल्में बना रहे हैं। जरूरत है सिर्फ सही रणनीति और मनोरंजन देने वाली कहानी की।" उन्होंने यह भी बताया कि अब छत्तीसगढ़ की फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करनी शुरू कर दी है और कई फिल्में हिंदी फिल्मों से ज्यादा व्यापार कर रही हैं।

शहरसत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी की प्रस्तुति

उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भविष्य उज्ज्वल है—बस कंटेंट और प्रस्तुति में दम होना चाहिए। सिंगल स्क्रीन सिनेमा आज भी लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, और अगर सरकार, सिनेमाघर मालिक और निर्माता मिलकर काम करें, तो क्षेत्रीय सिनेमा एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है।

कथानक बदला, नयापन शुरू, दौर बदल चला, ज़र्रा नवाजों तुम भी तो ज़रा बदलो

शेखर सोनी
कलाकार और निर्देशक

रायपुर। कहते हैं गर वक्त के साथ खुद को न बदलो तो वक्त तुम्हें बदल देगा। यही चीज छत्तीसगढ़ी सिनेमा मे देखने को मिल रही है। 25 साल होने को हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा को। मोर छंईहा भुंईहा से लेकर यादव जी के मधु जी तक का सफर कर चुका हमारा सिनेमा पटरी बदल चुका है। और यह बिजनेस के लिए शुभ संकेत है। ऐसे प्रयोग निश्चित होने चाहिए। बाकी की कुछ फिल्में भी चलनी थी मगर नही चलीं क्यों..मसला यहां सिनेमा का या कंटेंट कम आडियंस के माइंडसेट का ज्यादा है।

हमारे लिए मया से जुडा टाईटल और सब्जेक्ट सेफ साईड गेम है। और दर्शक भी मोहब्बत के चुटीले डबल मीनिंग गानों पर खुद को रिलेट करके जी रहा है । और सिनेमा भी इसी पर काम करते रहना चाहता हैं जरा भी लीक से हटने का जोखिम नही उठाना चाहता । दीगर सब्जेक्ट पर सिनेमा कम क्यों है कारण हम बनाते नही। डरते है कि फिल्म पिट जाएगी। ठीक है ऐसा हो भी सकता है लेकिन छत्तीसगढ़ी सिनेमा को टाइप्ड रोल टाइप्ड कथानक से एक दिन बाहर आना ही पडेगा। और सिनेमा बदलते ही दर्शक भी बदल जाएगा।

भले ही छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्री को आज यहां तक जिंदा लाने का काम सतीश जैन ने किया उनके अलावा इक्का दुक्का निर्देशक ही सुपरहिट की श्रेणी मे शामिल हो पाए। लेकिन आगे कब तक। हालांकि जिस रफ्तार से यहां फ़िल्म बन रही है उसी रफ्तार से 80% फिल्में मैदान मे धूल भी चाटती नजर आती हैं। कारण--- एक जैसी देखा देखी कहानियों की प्रस्तुति। कमजोर अभिनय और अनाडी निर्देशन। वैसे कुछ नये निर्देशक सचमुच बेहतरीन काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ कुछ। एक सवाल दर्शकों से भी कि वो भी क्यों नही बदलते उनका बदलना तो ज्यादा जरूरी है। सिनेमा प्रयोग से डरता है और दर्शक सिर्फ पैसा वसूल मनोरंजन चाहता है ग्यान नही। मेनू बदलिए भीड भी बढ़ेगी।

खैर इस पर और चर्चा करेंगे लेकिन यही कहना है कि अगर यादव जी जैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं तो वाकयी सिनेमा बदल रहा है। और यदि आफ बीट चटपटी कहानियां आती रही तो दर्शक भी बदल जाएंगे। दौर तो बदलता ही है। ज़र्रा नवाजों की भी इनायत हो जाए तो बस क्या है।

विरासत, भावना और तेज़ रफ्तार कहानी का जबरदस्त संगम

फ़िल्म समीक्षा : मोर छइहां भुंईया थ्री

छत्तीसगढ़ी सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म फ्रेंचाइज़ी 'मोर छइहां भुंईया थ्री ' का तीसरा भाग दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। यह फिल्म जहां अपने पहले दोनों भागों की विरासत को आगे बढ़ाती है, वहीं आधुनिक तकनीक, सशक्त स्क्रीनप्ले और भावनात्मक गहराई से एक नई ऊंचाई भी हासिल करती है।

कहानी वहीं से शुरू होती है जहां 'मोर छैयां भुईया 2' खत्म हुई थी। साहू परिवार अब शांत जीवन जी रहा है, लेकिन पुराने दुश्मन धर्मेंद्र चौबे की वापसी से नया बवाल खड़ा हो जाता है। विधायक बने नितिन ग्वाला को पड़ा एक थप्पड़ कहानी का रुख पूरी तरह मोड़ देता है। इसके बाद बदला, संघर्ष और रिश्तों की गहराई से जुड़ी घटनाएं दर्शकों को अंत तक बांधे रखती हैं।

सतीश जैन का निर्देशन उमदा है। 2000 से इस फ्रेंचाइज़ी को दिशा देने वाले सतीश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सबसे विश्वसनीय निर्देशक हैं। स्क्रीनप्ले कसावदार है और संवाद दिल को छूते हैं। जैसे राम का यह डायलॉग—"हर लड़की एक दिन मां बनथे... अउ मां ले खूबसूरत कोनो नई होए।" यह संवाद सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, संस्कृति की संवेदना है।

दीपक साहू का ड्यूल रोल दमदार है—हर फ्रेम में उनकी पकड़ दिखती है। अंजली चौहान और लक्षित झांजी की परफॉर्मेंस standout हैं, खासकर बच्चों की मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। भोजपुरी एक्ट्रेस ऋचा सिंह का डेब्यू भी फिल्म में ताजगी लेकर आता है। क्रांति दीक्षित और प्रकाश अवस्थी ने अपने किरदारों को प्रभावशाली तरीके से निभाया।

तकनिकी पक्ष देखें तो सिद्धार्थ सिंह की सिनेमैटोग्राफी, सूरज महानंद का प्रभावशाली बैकग्राउंड म्यूज़िक और तुलेंद्र की एडिटिंग—तीनों ने मिलकर फिल्म को तकनीकी रूप से भी मजबूत बना दिया है। 'सोना जैसे दिल' और 'दारू नई चढ़े' जैसे गाने पहले से ही हिट हैं, और फिल्म में ये गाने कहानी से जुड़ते हैं, रुकावट नहीं बनते। इसी तरह लाली, लाली लुगरा...गीत भी दर्शकों को कर्णप्रिय लगा।

कुछ खामियां भी हैं लेकिन दर्शक उसे अनदेखा कर गए। कहीं-कहीं किरदारों का अचानक गायब होना, उम्र का सही चित्रण न होना और कुछ दृश्यों में लॉजिक की कमी भी देखने को मिली। लेकिन फिल्म की भावनात्मक पकड़ और रफ्तार इन कमियों और खामियों को पीछे छोड़ देती है।

'मोर छैयां भुईया 3' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत का गर्व है। यह फिल्म दर्शाती है कि जब कहानी, भावना और तकनीक साथ चलें, तो क्षेत्रीय सिनेमा भी ग्लोबल स्टैंडर्ड को छू सकता है। फिल्म एक अनुभव है, एक जड़ से जुड़ी उड़ान है। इन शार्ट कहा जा सकता है कि फिल्म मोर छइहां भुंईया थ्री तीसरी बार भी पैसा वसूल साबित होगी।

बोर नहीं हुए दर्शक, सतीश ने बटोरी तारीफ

मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

सीएम साय ने झुरानदी में 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता और सरलता से झुरानदी गांव के ग्रामीण अभिभूत हो उठे। तपती दोपहरी में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अचानक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम झुरानदी में उतरा। बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीणों को हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ। मुख्यमंत्री ने गांव के बरगद पेड़ की छांव में चौपाल लगाई और बेहद आत्मीय अंदाज में ग्रामीणों से संवाद किया। देखते ही देखते पूरा गांव उमड़ पड़ा और माहौल उत्सव जैसा बन गया। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों से बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा कि मैंने बस्तर, सरगुजा के अनेकों जिले में और जांजगीर, चांपा, कबीरधाम, बेमेतरा जिले जैसे जिलों के सुदूर गांवों तक जाकर जनचौपाल की है। उन्होंने कहा कि आज मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी जिले से होकर आपके इस गांव झुरानदी में सीधे पहुंचा हूं। हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। हम हर घर तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की मांगों और समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए तथा योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर झुरानदी गांव में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने ग्राम में सीसी सड़क निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, दो उच्च स्तरीय पुल निर्माण-गंडई से कृतबाधा पहुंच मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ 54 लाख रूपए और गंडई कर्रानाला पहुँचमार्ग पर लिमो में उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 2 करोड 52 लाख रूपए और ग्रामीणों की मांग पर ग्राम पंचायत भोरमपुर में नए पंचायत भवन निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने गांव के बीच बाजार पड़ाव में बरगद पेड़ की छांव में जनचौपाल लगाई और वहां उपस्थित ग्रामीणों से छत्तीसगढ़ी भाषा में ही संवाद की शुरुआत की, जिससे ग्रामीणों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहराता गया। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं, सुझाव और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव भी सुने। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री साय के सहज, सरल, सादगीपूर्ण और विनम्र व्यवहार की खुले दिल से सराहना की। बुजुर्गों ने कहा कि वर्षों में पहली बार ऐसा अवसर आया है, जब प्रदेश के मुखिया सीधे उनके गांव में पहुंचे। किसानों और युवाओं ने मुख्यमंत्री

गांव में 180 पीएम आवास पूर्ण

खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत झुरानदी की जनसंख्या 1935 है। यह गांव लोधी एवं वर्मा समाज की बहुलता है। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। गांव में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और हाई स्कूल की सुविधा उपलब्ध है, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 217 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 180 पूर्ण हो चुके हैं तथा 37 निर्माणाधीन हैं। महतारी वंदन योजना से 616 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिल रहा है। गांव में 17 स्वसहायता समूह की महिलाएं आजीविका गतिविधियों से जुड़ी है।

योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने सुशासन तिहार बना कारगर : केदार कश्यप

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की परिकल्पना को साकार करते हुए चलाए जा रहे सुशासन तिहार ने प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य किया है। इसी कड़ी में आज बीजापुर के जैतालूर मार्ग स्थित हल्बा समाज भवन परिसर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया । वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने औचक निरीक्षण कर शिविर की कार्यप्रणाली का जायजा लिया।

मंत्री श्री कश्यप की अप्रत्याशित उपस्थिति से शिविर में नया जोश देखने को मिला। दीप प्रज्वलन कर उन्होंने शिविर का शुभारंभ किया और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। उन्होंने बताया कि बीते दो महीनों से चल रही इस पहल के तहत समाधान पेटियों के जरिए प्राप्त आवेदनों का न केवल निराकरण किया जा रहा है, बल्कि संबंधित नागरिकों को भी इसकी जानकारी दी जा रही है। शिविर में राजस्व विभाग के अंतर्गत जन्म के तुरंत बाद जाति प्रमाण पत्र की सुविधा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर घर में रसोई गैस, तथा गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु 5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा जैसी योजनाओं ने आमजन के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया है। श्री कश्यप ने कहा कि बीजापुर वह जिला है जहां कभी भय और आतंक का साया था, पर अब विकास की बयार बह रही है । सड़कें, पुल, बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। नगर पालिका बीजापुर अंतर्राल 5, 6 एवं 7 वार्ड में आयोजित शिविर में कुल 87 आवेदनों में से 75 का तत्काल निराकरण किया गया, जबकि शेष 12 आवेदनों पर कार्यवाही जारी है।

महिला समूह को मिला मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ

कोण्डागांव विकासखंड के ग्राम चिपावण्ड में आयोजित समाधान शिविर के दौरान मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन प्रसार कार्यक्रम अंतर्गत उन्नति महिला स्व-सहायता समूह को मछली पकड़ने का जाल प्रदाय किया गया। समूह की अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2011 में 14 सदस्यों के साथ समूह की शुरुआत की गई थी। उन्होंने ग्राम के तालाब को समूह के नाम स्वीकृत कराकर मछली पालन शुरू किया। इससे एक सीजन में लगभग 45 हजार रुपये का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

देव नारायण का बना राशनकार्ड

छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी पहल पर आयोजित सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बना है। इसी क्रम में सरगुजा जिले में आयोजित समाधान शिविर में ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी के निवासी श्री देव नारायण यादव का नया राशनकार्ड जारी किया गया। श्री देव नारायण यादव लंबे समय से राशनकार्ड के अभाव में शासकीय खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान अपनी मांग को लेकर सुशासन तिहार में आवेदन दिया। जिला प्रशासन ने मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए उनकी पात्रता की पुष्टि की और नया राशनकार्ड बनाकर प्रदान किया। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए देव नारायण यादव ने कहा, "अब मुझे और मेरे परिवार को शासकीय खाद्यान्न योजना का पूरा लाभ मिलेगा। सुशासन तिहार ने हमें अपनी समस्याएं सीधे शासन तक पहुँचाने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री आवास योजना से शंकर का सपना हुआ साकार

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। कांकेर जिले के पखांजूर विकासखण्ड के ग्राम पीवी 93 सिरपुर निवासी श्री शंकर बरकंदाज ने समाधान शिविर के मंच से अपने अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हुए परिवर्तन की जानकारी दी। अतिसंवेदनशील ग्राम छोटेबेठिया में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में श्री शंकर बरकंदाज ने बताया कि वे अत्यंत गरीब परिवार से हैं तथा पहले कच्चे मकान में रहने को विवश थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति दुर्बल होने के कारण पक्के मकान का निर्माण कर पाना उनके लिए असंभव था। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उनका प्रकरण स्वीकृत हुआ, जिसके फलस्वरूप आज उनका अपना पक्का मकान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है।

EV पॉलिसी धुंआ-धुंआ

विकास यादव/मुख्य संवाददाता

राज्य सरकार ने ई-वाहनों पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना बनाई थी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर समेत नवा रायपुर में भी जगह जगह चार्जिंग पॉइंट के लिए भी शासन प्रयासरत था। लेकिन सब्सिडी के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट में भी छत्तीसगढ़ पिछड़ता दिख रहा है। शासन, परिवहन विभाग समेत निगम की इस उदासीनता से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को धक्का लग सकता है। एक्सपर्ट्स की मानें तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में 28 प्रतिशत वायु प्रदूषण सिर्फ वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है।

6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री 25% बढ़ी

ई-कारों में 1.3% की ही बढ़ोतरी हुई

सब्सिडी में विलंब, प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को लगा धक्का

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के क्रियान्वयन में देरी से वाहन चालक परेशान

राज्य सरकार ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखा

इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू हुए दो साल बाद भी राशि अप्राप्त

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को लागू किए हुए दो साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में भारी लापरवाही सामने आ रही है। ई- बाइक, स्कूटर और इलेक्ट्रिक कारों के लिए घोषित सब्सिडी भी उपभोक्ताओं को समय पर नहीं दी जा रही हैं। इसके अलावा ई-व्हीकल्स के लिए राजधानी में पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट लगाने की प्रक्रिया भी धीमी है। अभी भी 45 हजार वाहन चालक ऐसे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन तो खरीद लिया, लेकिन अब तक उन्हें सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी नहीं मिली है। सरकार ने वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा है, जिससे प्रदूषण में 10 प्रतिशत की कमी लाने की योजना बनाई गई है। लेकिन सब्सिडी में हो रही देरी से सरकार की यह योजना धीमी होती नजर आ रही है। राज्य सरकार धुआं मुक्त वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजना बनाई है, लेकिन सब्सिडी के भुगतान में देरी इस योजना को कमजोर कर रही है।

सब्सिडी नीति कजोर तो प्रदुषण नियंत्रण मुश्किल

यदि सरकार अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सही समय पर लागू नहीं कर पाती, तो 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। सब्सिडी न मिलने से लोग ई-वाहनों की खरीद में रुचि नहीं लेंगे, जिससे पेट्रोल-डीजल वाहनों की निर्भरता बनी रहेगी और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास कमजोर होंगे।

वित्त विभाग की निष्क्रियता से हो रही देरी

परिवहन विभाग के अनुसार, सब्सिडी के भुगतान के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है और बजट मिलते ही इसका वितरण किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह बजट कब तक मिलेगा और वाहन चालकों को राहत कब मिलेगी? आयुक्त एवं सचिव, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ एस. प्रकाश के मुताबिक सब्सिडी भुगतान के लिए बजट प्रविधान के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। जैसे ही बजट मिलेगा, वैसे ही सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।

10% या अधिकतम 1.50 लाख रुपये तय है सब्सिडी

राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए चार पहिया और दो पहिया ई-वाहनों पर उनके मूल्य का 10 प्रतिशत या अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना बनाई थी। हालांकि, अब तक सिर्फ 28,248 वाहन चालकों को ही यह लाभ मिला है, जबकि 45 हजार लोग अभी भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

योजना अधर में, वाहनों से 28% प्रदूषण

विशेषज्ञों के अनुसार, रोड ट्रैफिक और वाहनों से निकलने वाला धुआं 45 से 53% तक वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यदि सिर्फ पीएम 2.5 (हवा में धूल, धुआं आदि के महीन कण) से होने वाले प्रदूषण को देखा जाए, तो इसमें अकेले वाहनों का योगदान 28% तक है।

एक नजर

- 5 साल में 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य तय था
- ई व्हीकल नीति के तहत 2027 तक रोड टैक्स में छूट
- EV पार्क में स्टार्टअप के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की योजना
- इलेक्ट्रिक वाहन-EV पार्क के लिए 5 सौ एकड़ एकड़ भूमि देना है
- चार्जिंग पॉइंट भी नया कारोबार बनेगा

छूट का प्रावधान

- रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ,
- EV के निर्माण के लिए SGST प्रतिपूर्ति,
- EV चार्जिंग के लिए बिजली शुल्क
- EV इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी-इंसेंटिव
- शासन देगी प्लांट-मशीनरी की लागत का 25% अनुदान

EV चार्जिंग पॉलिसी में भी पिछड़ गए

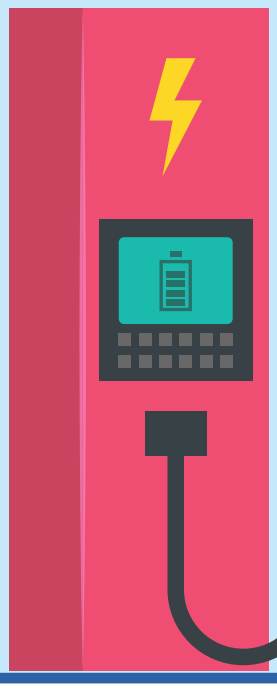

- पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये सार्वजनिक और निजी ऑपरेटरों को आमंत्रित किया जाना
- राज्य के सभी शहरों में नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन जमीन
- चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिये स्थानों की सूची राज्य EV विकास निगम तैयार करेता
- हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंपों (रीफ्यूलिंग स्टेशन) को फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिये प्रोत्साहित करना
- दो पहिया वाहनों के लिये मुफ्त या प्राथमिकता वाली पार्किंग के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना
- फ्लायओव्हर के निचे पार्किंग और सरकारी कार्यालयों के पार्किंग क्षेत्रों में भी चार्जिंग प्वाईंट बनाना
- मॉल, हाउसिंग बोर्ड के भवनों, आवासीय समितियों, आवासीय नीति में भी चार्जिंग पॉइंट शामिल होगा

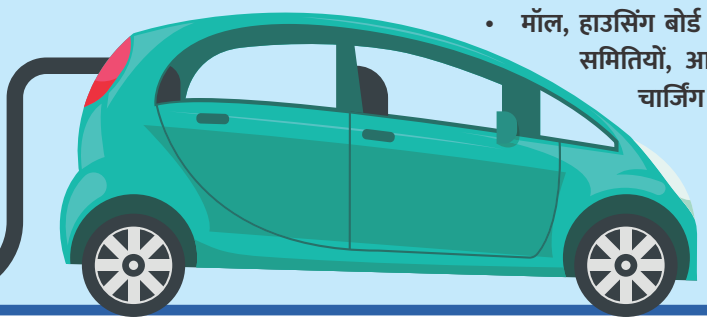

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-22683361, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी।